वर्ष-06 | अंक-02 | दिसंबर 2025 | पृष्ठ संख्या-40

RNI No. : DELBIL/2020/87310

www.imagenews.in

नई दिल्ली से प्रकाशित ₹15

THE IMAGE BRANDING

दिल्ली धमाका

धुएं के गुबार में खोई उम्मीदें

NM Media Solutions

Design
Solutions

Website
Development

Content
Writing

Help you to
Grow your **Business**

www.nmmediasolutions.in
VISIT OUR WEBSITE

More Info Call Us:
9717177725

Expert in Print and Digital Media

15, Aurobindo Apartments,
Adhchini, New Delhi-110017

nmmediasolutions@gmail.com
admin@nmmediasolutions.in

THE IMAGE BRANDING
RNI No. : DELBIL/2020/87310
Volume-06, Issue-02 | December 2025 | ₹ 15

Editor
Ajit Kumar Verma

Senior Associate Editor
Shruti Verma

Assistant Editor
Rachit Verma

Editorial Assistance
Shailendra Kumar

Design & Production
NM Media Solutions, Delhi

Patna Bureau Chief
Gyan Kumar Singh

Patna Correspondent
Anish Kumar

Delhi Correspondent
Kamal kumar

Tax Consultant
Manoj Kumar Sinha

Video Technical Head
Vikas kumar

Regd. Office
A-43, 2nd,Floor, Right Portion, Amrit Nagar, Kotla, New Delhi-110003
Mob. No. +91-8800224261
E-mail: ajeetv@hotmail.com
website : www.imagenews.in

Owned and published by Ajit Kumar Verma, A-43, 2nd,Floor, Right Portion, Amrit Nagar, Kotla, New Delhi-110003, and printed at C-114 , Gate No.-1, Back Side, Naraina, Industial Area-I, New Delhi-110028

पत्रिका से संबंधित सभी तरह के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

06 दिल्ली धमाका धुएं के गुबार में खोई उम्मीदें

12 बिहार विधानसभा चुनाव ने बदल दिया राजनीतिक परिदृश्य

14 बिहार का जनादेश, जाति की जगह स्थिरता को प्राथमिकता

16 विधेयकों की मंजूरी पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

18 सियासत वाली पराली

24 पुतिन की भारत यात्रा और समझौते

28 जेएनयू छात्र संघ चुनाव में कैसे 'राइट' पर भारी पड़ा लेफ्ट

30 धर्मेंद्र—एक र ुग का अंत

32 क्या शुरू होगी नई न्यूक्लियर रेस?

36 नारद मुनि कहिन

38 मल्लिका ने खोला फिल्म इंडस्ट्री का काला सच

बीते वर्षों में भारत समेत दुनिया के कई देशों ने जिस खतरे का सामना किया है, वह केवल सीमाओं पर मौजूद नहीं है - वह डिजिटल स्पेस, सोशल मीडिया नेटवर्कों और बंद-कमरों वाली विचारधारा संबंधी कार्यशालाओं में भी पल रहा है। कट्टरपंथी तत्व अब उन पेशों को भी निशाना बना रहे हैं जिन्हें समाज ने सबसे ज्यादा भरोसे, संवेदनशीलता और मानवता से जोड़ा है- जैसे डॉक्टर, नर्स और मेडिकल विद्यार्थी। चिकित्सा-पेशा अपने मूल में जीवन-रक्षक है। लेकिन जब किसी भी विचारधारा के उग्रवादी तत्व इसे अपनी विचारधारात्मक भर्ती का मंच बनाने की कोशिश करते हैं, तो यह समाज और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के लिए बेहद खतरनाक स्थिति बन जाती है। यह प्रवृत्ति नई नहीं है, परंतु हालिया तकनीकी साधनों ने इसे आसान और तेज बना दिया है।

कट्टरपंथ की नई रणनीतिः उग्रवादी संगठनों की रणनीतियों का अध्ययन दिखाता है कि वे अब ऐसे वर्गों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जो—उच्च शिक्षित, आर्थिक रूप से सुरक्षित,सामाजिक रूप से सम्मानित, और संवेदनशील मुद्दों से प्रभावित होने की संभावना रखते हैं। ऐसे वर्गों में चिकित्सा-समुदाय एक आसान लक्ष्य बन सकता है यदि संस्थागत निगरानी, परामर्श तंत्र और मानसिक-स्वास्थ्य समर्थन कमजोर हो। कट्टरपंथी नेटवर्क अक्सर विकृत धार्मिक व्याख्याओं, गलत ऐतिहासिक दावों, पीड़ित-मनोवृत्ति को बढ़ावा देने वाले आख्यानों, और 'न्याय के नाम पर हिंसा' को महिमामंडित करने वाले संदेशों के माध्यम से युवाओं को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं।

भारत-विरोधी नैरेटिव का निर्माणः भारत जैसे विविध और लोकतांत्रिक देश में असहमति और बहस लोकतंत्र का हिस्सा है, परंतु जब असंतोष को हिंसात्मक, उग्रवादी या आतंकी एजेंडे का औजार बनाया जाता है, तो यह किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं हो सकता। यदि किसी भी पेशे—विशेषकर डॉक्टरों—को ऐसी गतिविधियों में खींचने की कोशिश हो, तो यह न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा बल्कि जनता के विश्वास पर सीधा प्रहार है। एक उग्रवादी डॉक्टर या चिकित्सा-विद्यार्थी का मतलब हैः अस्पतालों की सुरक्षा पर खतरा, संवेदनशील जानकारी का दुरुपयोग,तथा लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़।

क्या करना जरूरी हैः मेडिकल संस्थानों में डिजिटल-सुरक्षा व काउंसलिंग तंत्र मजबूत हों—क्योंकि कट्टरपंथ अक्सर ऑनलाइन शुरू होता है। धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता पर आधारित संवाद को चिकित्सा-शिक्षा में औपचारिक रूप से शामिल किया जाए। सुरक्षा एजेंसियों व विश्वविद्यालयों के बीच समन्वय बढ़ाया जाए, ताकि शुरूआती स्तर पर किसी भी संदिग्ध गतिविधि की पहचान हो सके। मेडिकल छात्रों व डॉक्टरों के लिए मानसिक-स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध हो, ताकि अकेलेपन या तनाव को कट्टरपंथी तत्वों द्वारा exploit न किया जा सके। दुष्प्रचार के खिलाफ जागरूकता अभियान क्योंकि कट्टरता की पहली सीढ़ी अक्सर गलत सूचना होती है।

डॉक्टरों, अध्यापकों, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों सहित कोई भी वर्ग इस खतरे से अछूता नहीं है। परंतु समाधान 'संदेह के माहौल' में नहीं, बल्कि पारदर्शिता, संवाद और विवेकपूर्ण निगरानी में है। समाज को समझना होगा कि उग्रवाद का कोई मजहब या पेशा नहीं होता—लेकिन उसका सबसे बड़ा हथियार कमजोर मनोभूमि और गलत सूचना होती है। यदि हम इस हथियार को प्रभावहीन बना दें, तो न केवल चिकित्सा-समुदाय बल्कि पूरा देश अधिक सुरक्षित होगा।

अजीत कुमार वर्मा

चिकित्सा-पेशा अपने मूल में जीवन-रक्षक है। लेकिन जब किसी भी विचारधारा के उग्रवादी तत्व इसे अपनी विचारधारात्मक भर्ती का मंच बनाने की कोशिश करते हैं, तो यह समाज और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के लिए बेहद खतरनाक स्थिति बन जाती है।

www.imagenews.in

नई दिल्ली से प्रकाशित

THE IMAGE BRANDING

राज, समाज, साहित्य, संस्कृति, कला
एवं पर्यटन की राष्ट्रीय पत्रिका

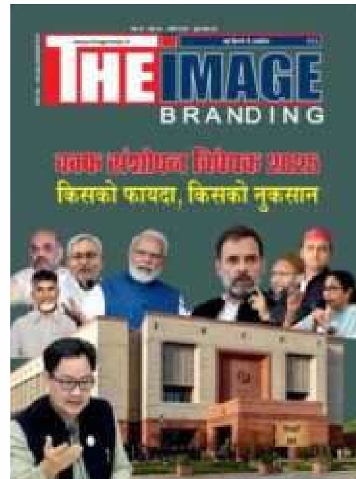

आप भी अपना विज्ञापन
देकर कारोबार को बढ़ाएं

हर स्टोरी में कोई न कोई कहानी होती है, जिसे हम आपको अपनी पत्रिका के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। हम आपके लिए हर अंक में कुछ खास देने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसा जो आपको अच्छा लगे।

Follow us

www.imagenews.in

नई दिल्ली से प्रकाशित

THE IMAGE BRANDING

Regd. Office : A-43, 2nd,Floor, Right Portion,
Amrit Nagar, Kotla, New Delhi-110003

Mob. No. +91-8800224261
E-mail: ajeetv@hotmail.com
website : www.imagenews.in

दिल्ली धमाका
धुएं के गुबार में खोई उम्मीदें

राजधानी दिल्ली में हुए आत्मघाती कार बम विस्फोट सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय चेतावनी है, जो पढ़े-लिखे और समझदार लोगों का ब्रेनवॉश कर उन्हें आतंकी गतिविधियों में शामिल करने की साजिश है।

जांच के बाद जो तथ्य सामने आए हैं उससे स्पष्ट है कि लाल किला के पास हुए विस्फोट का संबंध पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद मॉड्यूल से है। इसमें उमर मोहम्मद और उसके कई साथी शामिल थे। अधिकारियों ने अमोनियम नाइट्रेट और ईंधन तेल जब्त किया है, जो हमले में इस्तेमाल किए गए विस्फोटकों इस्तेमाल किए गए। एनआईए, एनएसजी, दिल्ली पुलिस सहित सुरक्षा एजेंसियां, जम्मू-कश्मीर पुलिस के सहयोग से, संयुक्त रूप से मामले की जांच कर रही हैं। शीर्ष खुफिया सूत्रों की अब तक की थ्योरी के मुताबिक दिल्ली के लाल किले के पास हुआ विस्फोट अफरा-तफरी के कारण हुआ था, जिसकी जांचकर्ताओं ने भी पुष्टि की।

बताया जाता है कि कि पूरे भारत और फरीदाबाद में सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई के चलते संदिग्ध आतंकियों को डर था कि वे पकड़े जा सकते हैं। इसी वजह से विस्फोटक दूसरी जगह ले जाने या निपटाने की कोशिश की जा रही थी, जो गलती से फट गया। माना जा रहा है कि यह आत्मघाती मिशन हो भी सकता है लेकिन पूरी संभावना ये है कि यह आकस्मिक विस्फोट था। धमाके के समय वाहन चल रहा था और आईईडी भी पूरी

तरह तैयार नहीं थी। लाल किला विस्फोट की कड़ियां अंततः श्रीनगर में पोस्टरों के मिलने से जुड़ रही हैं। इसके बाद कश्मीर और फरीदाबाद में कई गिरफ्तारियां हुईं।

इस मामले में 20 से 27 अक्टूबर के बीच शोपियां से मौलवी इरफान अहमद वाघे और गांदरबल के वाकुरा से जमीर अहमद की गिरफ्तारी हुई। सूत्र ने बताया कि पांच नवंबर को सहारनपुर से डॉ. अदील को पकड़ा गया और सात नवंबर को अनंतनाग अस्पताल से एके-56 राइफल तथा गोला-बारूद जब्त किया गया।

8 नवंबर को हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल-फलाह मेडिकल कॉलेज से भी हथियार और बारूद जब्त किए गए। पूछताछ के दौरान मिली

सूचनाओं से इस मॉड्यूल में शामिल अन्य आरोपियों के बारे में पता चला, जिसके बाद डॉ. मुजम्मिल को अल-फलाह मेडिकल कॉलेज से दबोचा गया।

सूत्रों ने बताया कि 9 और 10 नवंबर को सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने के बाद तीन चिकित्सकों सहित आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया और 2,900 किलोग्राम बम बनाने की सामग्री जब्त की गई। डॉ. उमर नबी उस आई 20 कार को चला रहा था, जिसमें विस्फोट हुआ। मारे गए लोगों में वह शामिल है। उमर भी अल फलाह मेडिकल कॉलेज से जुड़ा था और माना जा रहा है कि उसने कथित तौर पर यह आतंकी हमला इसलिए किया, क्योंकि उसे डर था कि वह भी अपने साथी चिकित्सकों की तरह पकड़ा जा सकता है। विस्फोट के एक दिन बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने उमर की मां का डीएनए नमूना लिया, और अवशेषों से उसकी मौत की पुष्टि की।

फरीदाबाद से लगभग तीन टन विस्फोटक बरामदगी के साथ जिन तीन डॉक्टरों सहित आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया उन सभी के तार तीन राज्यों- जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से जुड़े थे। वे आतंकी गतिविधियों में शमिल थे और बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। लेकिन गिरफ्तार किए गए ये सभी पारंपरिक आतंकवादी नहीं हैं बल्कि उच्च शिक्षित डॉक्टर और शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग हैं। इनमें एक महिला डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी और पूछ-ताछ से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी संगठनों की महिला शाखा की संलिप्तता का पता चला है। साथ ही जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों से आरोपियों के जुड़ाव का भी संकेत मिला है।

घबराहट में किया गया कार में ब्लास्ट

माना जा रहा है फरीदाबाद में जारी कार्रवाई के बाद डॉ. उमर मोहम्मद घबरा गया था। वह एक अधूरी बम डिवाइस (IED) को कहीं और ले जाने या रास्ते में फेंकने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान गाड़ी चलते-चलते धमाका हो गया। जांच में यह भी सामने आया है कि धमाके में कोई गड्ढा नहीं बना और न ही कोई भारी चीज (प्रोजेक्टाइल) मिली। अधिकारियों का कहना है कि अगर देशभर में पहले से चल रही कड़ी निगरानी और सुरक्षा जांच नहीं होती तो हमला कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता था।

जांच एजेंसियों का मानना है कि ये धमाका पैनिक अटैक का हिस्सा लगता है, क्योंकि आतंकी डॉक्टरों की टीम पुलिस के रडार पर आ चुकी थी और डॉ. उमर मोहम्मद की लोकेशन लगातार ट्रेस की जा रही थी। डॉ. उमर को पता था कि उसके बाकी साथी पकड़े जा चुके हैं, विस्फोटक बनाने का सामान पकड़ा गया है। तो वो भी जल्द ही पकड़ा जाएगा। जांच

एजेंसियों का दावा है कि हमले की साजिश बहुत बड़ी थी। नुकसान बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता था, लेकिन समय रहते कार्रवाई के चलते नुकसान कम हुआ। देश के कई राज्यों में जांच एजेंसियों की छापेमारी अब भी जारी है और संदिग्धों की तलाश की जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि इस ब्लास्ट का हैंडलर कौन था? जांच एजेंसियों को इसमें तुर्की माड्यूल,पाकिस्तानी माड्यूल और कुछ मायनें में बांग्लादेशी माड्यूल का हाथ होने का भी शक है। गृह मंत्रालय ने जांच NIA को सौंप दी है और जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट देने को कहा गया है।

कैलिबर के तीन कारतूस मिले

दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक लाल किले के पास कार ब्लास्ट वाली जगह से 9mm कैलिबर के तीन कारतूस भी मिले। इनमें से दो जिंदा कारतूस है और एक खाली खोखा है। ये कारतूस आमतौर पर फोर्सेज या पुलिसकर्मी ही इस्तेमाल करते हैं।

सबसे बड़ी बात ये है कि मौके से पुलिस को कोई पिस्तौल या उसका कोई पार्ट नहीं मिला है। यानी गोली के कारतूस तो मिले, पर उन्हें चलाने वाला हथियार अभी तक नहीं मिला है।

हवाला से आया पैसा

केंद्रीय जांच एजेंसियां यह पता लगा रही हैं कि क्या इस टेरर मॉड्यूल को फंड करने के लिए हवाला या अवैध मनी चैनल का इस्तेमाल हुआ था। जांच में अब तक सामने आया है कि मुख्य आरोपी उमर को लगभग 20 लाख रुपये अवैध वित्तीय चैनलों के जरिए मिले थे। कुछ हवाला डीलर्स को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आरोपी डॉक्टरों ने नूंह में बाजार से बड़ी मात्रा में फर्टिलाइजर कैश में खरीदे थे।

200 से ज्यादा डॉक्टरों पर नजर

जांच एजेंसियां व्हाइट कॉलर मॉड्यूल को पकड़ने के लिए देशभर में करीब 200 डॉक्टरों पर नजर रखे हुए हैं और इनमें से कई को हिरासत में लिया जा चुका है। यह वो डॉक्टर हैं, जो डॉ उमर और शाहीन के संपर्क में आए थे। इनमें से कई के फोन बंद जा रहे हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि उमर लोगों का ब्रेन वॉश करता था और साथी डॉक्टर को रेडिकलाइज

करने की कोशिश करता था। कुछ ऐसे लोगों के बारे में जानकारी मिली है, जिनका ब्रेनवाश किया गया, उन्हें कट्टर सोच का बनाया गया।

फर्जी लेन-देन, 1 पते पर 9 कंपनियां

ईडी फंडिंग की जांच कर रही है। यह कार्रवाई अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं, शेल कंपनियों के इस्तेमाल, फर्जी लेन-देन और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का हिस्सा है। छापों के दौरान अधिकारियों ने ग्रुप से जुड़ी 9 संदिग्ध शेल कंपनियों की गतिविधियों को फोकस में लिया है, जो सभी एक ही पते पर रजिस्टर्ड पाई गईं। शुरूआती जांच में कई ऐसे पैटर्न सामने आए हैं, जो शेल कंपनी संचालन की ओर इशारा करते हैं।

यूजीसी व एनएएसी मान्यता पर भी सवाल

यूजीसी और एनएएसी मान्यता को लेकर ग्रुप द्वारा किए गए दावों में भी प्राथमिक स्तर पर कुछ गड़बड़ियां पाई हैं। इस पहलू पर अलग से पड़ताल की जा रही है और आगे मिलने वाली जानकारियों के आधार पर जरूरी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने जांच और जालसाजी एवं धोखाधड़ी के लिए विश्वविद्यालय के खिलाफ दर्ज दो मामलों में अल फलाह विश्वविद्यालय प्रशासन को समन जारी किए थे।

एजेंसियों ने पाया कि विश्वविद्यालय के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी का बयान संस्थान के कामकाज और उससे जुड़े व्यक्तियों की गतिविधियों से संबंधित कई विसंगतियों को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण है जो लाल किले के पास हुए विस्फोट की जांच से संबंधित है। माना जा रहा है कि विस्फोट से जुड़े कई संदिग्धों का विश्वविद्यालय से संबंध रहा है, जिसके कारण जांचकताओं को संस्थागत रिकॉर्ड, वित्तीय लेन-देन और प्रशासनिक स्वीकृतियों की जांच जरूरी है।

अवैध निर्माण पर जल्द चल सकता है बुलडोजर

जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे अल-फलाह यूनिवर्सिटी का मामला भी गमार्ता जा रहा है। जांच एजेंसियों को शक है कि यूनिवर्सिटी के विस्तार में बड़े पैमाने पर नियमों की अनदेखी हुई है। इसी वजह से अब प्रशासन ने यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।

पाया गया है कि कई निर्माण बिना मंजूरी या फिर नियमों की अनदेखी करके किए गए हैं। एजेंसियों का ध्यान अब यूनिवर्सिटी के फंड, पैसों के लेनदेन और किसी भी तरह की आतंकी गतिविधियों से जुड़े संभावित लिंक पर है। यूनिवर्सिटी के अवैध निर्माण पर जल्द ही बुलडोजर चल सकता है।

हालांकि गिरफ्तार डॉक्टरों के बयान से इस पूरे सिलसिले में ये स्थापित हो गया है कि उन्हें अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्म का हवाला देकर चरमपंथ की ओर धकेला गया। देश में इस बात को लेकर अधिक चिंता है कि मानव जीवन को बचाने के पेशे से जुड़े डॉक्टरों का इस्तेमाल दहशदगर्दी और व्यापक जनहत्या के लिए किया गया। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह सहित वहां की सभी पार्टियों ने इसकी घोर निंदा की। उन्होंने कहा कि इससे देश के अन्य शहरों में पहुंचने वाले जम्मू कश्मीर के निर्दोष निवासियों को भी शक और शुबहा का सामना करना पड़ेगा।

NSM-400

कार में धमाका नहीं, कुछ और थी प्लानिंग

हरियाणा के फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में लगातार खुलासे हो रहे हैं। अब एक और खुलासा हुआ है, जिसमें पता चला है कि आतंकियों की कार ब्लास्ट की नहीं, हवाई हमले की प्लानिंग थी। ड्रोन से यह हमला करने की प्लानिंग थी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) की टीम हाल ही में दिल्ली ब्लास्ट में शामिल कश्मीरी छात्र जसीर बिलाल वानी को निशानदेही के लेकर अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची और उसे विस्फोटक रखने वाली जगहों ले जाकर निशानदेही करवाई गई, जानकारी के मुताबिक, जसीर वानी ने आटा-चक्की से यूरिया को पीसकर, उसमें से अमोनियम नाइट्रेट अलग करने में आतंकी मुजम्मिल की मदद की थी। जसीर वानी के साथ एजेंसी डॉ. शाहीन और डॉ. मुजम्मिल को भी लेकर आई थी, लेकिन केवल जसीर वानी को गाड़ी से उतारकर निशानदेही कराई गई। जसीर वानी डॉ. मुजम्मिल के साथ उसके फ्लैट पर भी रुका था। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) अपने साथ बम निरोधक दस्ते को भी साथ लेकर आई थी। यूनिवर्सिटी परिसर के साथ लगते लगभग दो एकड़ के खेत में बने कमरे की जांच बम निरोधक दस्ता ने जांच की। 12 दिन तक विस्फोटक सामग्री को इसी कमरे में रखा गया था और फिर फतेहपुर तगा का शिफ्ट किया था। टीम ने यहां कमरे के अंदर और पास में मिट्टी खोदकर जां। की। फिर डॉ. मुजम्मिल और शाहीन को यूनिवर्सिटी के एडमिन ब्लॉक में ले जाकर रखा गया।

गांव धौज में रखी गई थी आटा चक्की: गांव धौज में एनआईए की टीम जसीर वानी को डॉ. मुजम्मिल के फ्लैट में ले गई और गांव खोरी जमालपुर में पूर्व सरपंच के मकान के मुजम्मिल ने 3 कमरों किराए पर लिए थे, यहां पर भी निशानदेही करवाई गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जसीर वानी (20) पुलवामा का रहने वाला है और अनंतनाग के कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड ईयर का छात्र है। वह दिल्ली ब्लास्ट में खुद को उड़ाने वाले आतंकी उमर का सबसे ज्यादा करीबी रहा। डॉ. शाहीन और मुजम्मिल से जसीर वानी की मुलाकात आतंकी उमर ने कराई थी। **हवाई हमले की थी प्लानिंग:** जसीर वानी से एजेंसी की पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ है कि पहले हवाई हमले की प्लानिंग की गई थी, जिसमें विस्फोटक को भरकर दूर से ही हमले को अंजाम दिया जा सके, लेकिन ऐसा नही हो पाया, जिसके बाद उमर ने अपने साथियों के साथ दिल्ली में कई जगहों पर एक साथ हमले की योजना बनाई थी।

श्रीनगर में प्लान तैयार, कुछ प्रयोग भी किए : इसके लिए कश्मीर के श्रीनगर पूरा प्लान तैयार किया गया था। जहां पर कुछ प्रयोग भी किए गए थे, लेकिन बजट ज्यादा होने के चलते ऐसा संभव नही हो पाया, जसीर वानी के पुलवामा स्थित गांव से कुछ दूर ही आतंकी मुजम्मिल का भी गांव है।

-द इमेज ब्रांडिंग

बिहार विधानसभा चुनाव ने बदल दिया राजनीतिक परिदृश्य

नीतीश कुमार की लोकप्रियता और विकास कार्यों से जेडीयू ने 85 सीटें जीतकर 2010 के बाद अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हुए जातीय समीकरण में फंसे विपक्ष को परास्त कर दिया। हालांकि प्रदेश के मुस्लिम मतदाताओं ने विकल्प के तौर पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का दामन थामा। इस पार्टी ने महागठबंधन के वोट काटे, जो आरजेडी के लिए बड़ा झटका साबित हुआ।

बिहार में 6 और 11 नवंबर 2025 को दो चरणों में संपन्न विधानसभा चुनाव से राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह बदल गया है। चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 202 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया, जबकि एमवाई समीकरण और जाति का असर कम होने से महागठबंधन केवल 35 सीटों पर सिमट गया।

भाजपा ने 89 सीटें जीतकर पहली बार बिहार में सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हासिल किया, जबकि आरजेडी 25 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर खिसक गई। चुनाव नतीजों में भाजपा को 89, जेडीयू को 85, लोजपा को 19, हम 5 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 4 समेत कुल 202 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की। वामपंथी दल, बागी उम्मीदवार और दलबदलु नेता कुछ खास असर नहीं डाल सके। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल सकी और उसके सारे दावे हवा-हवाई साबित हुए।

बिहार के इतिहास में यह चुनाव सबसे शांतिपूर्ण रहा, जहां कोई

पुनर्मतदान नहीं हुआ। मतदान के दौरान कोई हिंसक वारदात नहीं हुई। इस चुनाव में 67.13% मतदान दर्ज किया गया, जो 1951 के बाद से बिहार के चुनावी इतिहास में सबसे अधिक है। पिछले चुनाव की तुलना में यह 9.84% अधिक है। इस चुनाव में महिलाओं की अभूतपूर्व भागीदारी रही।

नीतीश कुमार की लोकप्रियता और विकास कार्यों से जेडीयू ने 85 सीटें जीतकर 2010 के बाद अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हुए जातीय समीकरण में फंसे विपक्ष को परास्त कर दिया। हालांकि प्रदेश के मुस्लिम मतदाताओं ने विकल्प के तौर पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का दामन थामा। इस पार्टी ने महागठबंधन के वोट काटे, जो आरजेडी के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। एआईएमआईएम ने सीमांचल के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में 5 सीटों पर जीत हासिल कर भविष्य की राजनीति में अपना प्रभाव बढ़ाने के संकेत दिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बसपा ने भी एनडीए की जीत में महत्पूर्ण भूमिका निभाई। यूपी सीमा के आसपास के विधानसभा क्षेत्रों में बसपा का व्यापक प्रभाव दिखा। मायावती के नेतृत्व वाली पार्टी बीएसपी ने कुल 181 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन सिर्फ एक सीट रामगढ़ पर जीत हासिल कर सकी पर उसने चुनाव में पिछड़े, मुस्लिम और दलित वोट बैंक को विभाजित किया जिसने विपक्षी गठबंधन को नुकसान पहुंचा। महा गठबंधन के सिर्फ 35 सीटों पर सिमटने में बसपा की बड़ी भूमिका रही। चुनाव के बाद एनडीए ने नीतीश कुमार को अपना नेता चुना जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की10वीं बार शपथ ली,जो भारतीय राजनीति में एक रिकॉर्ड है।

-द इमेज ब्रांडिंग

बिहार का जनादेश, जाति की जगह स्थिरता को प्राथमिकता

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से प्रदेश की राजनीति फिर से भविष्य के विकास पथ पर कदम बढाने की ओर उन्मुख हो गई है। वहां मतदाताओं ने दृढ़ राजनीतिक परिपक्वता के साथ अपना जनादेश सुनाया है। बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव गहरा राजनीतिक संदेश देता है। इसने नीतीश कुमार के सुशासन के प्रति लोगों की स्पष्ट राय की पुनर्पुष्टि कर दी। इसने बेमतलब और बेमकसद के जातीय राजनीतिक धुर्वीकरण की जगह स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा को तरजीह दी। बिहार का जनादेश दर्शाता है कि वहां के मतदाता भावनात्मक उद्वेग, जातिगत उत्तेजना और फर्जी चुनावी वादों के जाल में फंसने वाले नहीं हैं। उनकी केवल उसी नेतृत्व के प्रति आस्था और विश्वास है जो उनके जीवन में सुरक्षा प्रदान करे और जमीनी स्तर पर विकास के काम करे। 243 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के 122 सीटों के आंकड़े को जनता ने गणितीय संख्या भर माना। उसने एनडीए को ऐसा प्रचंड बहुमत दिया कि महागठबंधन के सभी पूवार्नुमान और उम्मीदे धराशायी हो गईं और वह पचास सीटें भी हासिल ना कर सका। तेजस्वी यादव जो खुद को अगला मुख्यमंत्री मान रहे थे, उन्हें और उनकी पार्टी आजेडी को जनता ने पूरी तरह नकार दिया।

महागठबंधन और खास तौर पर राष्ट्रीय जनता दल की पराजय किसी एक नेता की हार नही बल्कि उस जातिगत और समूह-विशेष राजनीतिक रणनीति की विफलता है जो केवल जातिगत नारों, पूरा न हो सकने वाले वादों और सहयोगी दलों की टांग खींच कर गिराने पर टिकी थी। 2020 में कुछ हजार वोटों से मात खाने वाली आरजेडी को उम्मीद थी कि लोग इस बार उसे सत्ता की चाबी सौंप देंगे, पर 2025 के चुनाव ने उसके सपने तोड़ दिए।

इस चुनाव में आरजेडी नेतृत्व वाले महागठबंध की हार का मुख्य कारण लालू परिवार के पुराने भ्रष्टाचार के मामले, जंगल राज का कुशासन और गठबंधन प्रबंधन की विफलता रही। महागठबंधन में शुरू से ही छेद नजर आ रहा था, भीतर से बिखरा हुआ था और झटकों से गिरने वाला था। उसका कांग्रेस से सीट बंटवारे पर तकरार भी दिख रहा था। पिछले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने वाले वाम दलों को कमजोर सीट देना और प्रचार में सहयोगियों को हाशिए पर रखना और भितरघात की कोशिशें करना- इन सबने गठबंधन में असंतोष और अविश्वास पैदा कर दिया। इसका सबसे खराब पहलू रहा महागठबंधन का घोषणापत्र को तेजस्वी प्रण के नाम से जारी किया जाना। इस कदम ने साझेदारी और संयुक्त दायित्व की भावना ध्वस्त कर दी। उधर कांग्रेस गारंटी पर गारंटी दिए जा रही थी वाम दल किसान-मजदूर के मुद्दों को उभार रहे थे पर तेजस्वी कर रहे थे नौकरी के वादे। एनडीए ने इसकी काट में कहा कि ये नौकरी देंगे तो आपकी जमीन ले लेंगे। और अब नौकरी कहां से देंगे ऊपर तो हम बैठे हैं। इन्हीं वजहों से महागठबंधन साझा दृष्टिकोण नहीं पेश कर सका और चुनाव में कभी एक जुट नहीं दिखा। तेजस्वी के वादे अविश्वसनीयता से भरे रहे। हर घर में नौकरी, पेंशन, शराबबंदी खत्म करना, महिलाओं को आर्थिक मदद जैसे वादे पूरा करने-कराने का सामर्थ्य और उनका क्रियान्वयन लोगों को हवाई

लगा। इनके लिए वित्तीय स्रोत या समय सीमा के बारे में उनके पास कोई जवाब नहीं था। युवा और शहरी मतदाताओं ने भी इसे महज छलावा माना और राजद के लिए उनके मन में कोई उत्साह नहीं जगा।

महागठबंधन की मुस्लिम परस्त छवि ने उसका नुकसान और बढ़ा दिया। उसे मुस्लिम बहुल सीटों पर तो कुछ लाभ मिला पर पूरे राज्य के वोटरों में यह छवि नुकसानदायक साबित हुई। वक्फ कानून लागू ना करने की घोषणा और इसी तरह के कई संवेदनशील बयानों ने उनके कोर वोटर यादव समुदाय के एक वर्ग को भी विचलित कर दिया। एनडीए ने इसे भुनाते हुए लालू यादव के पुराने बयानों को जनता के सामने रख दिया जिसके वायरल होने से जनमत प्रभावित हुआ। गैर मुस्लिम-गैर यादव वोटों ने निर्णायक मोड़ पर महागठबंधन का साथ छोड़ दिया। तेजस्वी यादव के लिए दुखदायक और राजनीतिक गलती आरजेडी के पुराने पापों की विरासत भी रही। वे लालू प्रसाद के उत्तराधिकारी की विरासत साथ लेकर भी चले और उनके पूर्व शासन पद्धति से दूरी भी बनाते दिखे मगर जनता में भरोसा नहीं जगा सके।

महिलाओं ने चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और एनडीए की जीत सुनिश्चित कर दी। बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरूषों से 9 प्रतिशत अधिक रहा। जीविका समूह की एक करोड़ से अधिक महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण,10 हजार रुपये की सहायता, 2 लाख रु. की उद्यम सहायता से पिछड़े वर्ग सहित समाज के सभी वर्ग की महिला मतदाता नीतीश सरकार जारी रखने के समर्थन में लामबंद हो गईं। बिहार के आम मतदाता भी सुरक्षा व्यवस्था,सड़क-बिजली में सुधार, स्वास्थ सेवाओं को संभाले रखने के प्रयास, महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल और भविष्य में विकास की आशा से एनडीए के पक्ष में झुके। उन्हें लगा कि तेजस्वी युवा व ऊर्जावान तो हैं पर उनकी राजनीति जाति आधारित है। उनमें राज्य के विकास के प्रति ठोस योजना का अभाव है और स्थिरता की कोई गारंटी नहीं है।

यह जनादेश सही मायनों में एनडीए की जीत से ज्यादा बिहार की राजनीतिक परिपक्वता का प्रमाण है। जनता ने स्पष्ट कर दिया कि उसे घोषणा नहीं विश्वास, जाति नहीं स्थिरता, बलजोरी नहीं सुशासन चाहिए।

झारखंड स्थापना दिवस

झारखंड स्थापना दिवस हर साल 15 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन, 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर यह भारत का 28वां राज्य बना था, और यह दिन महान जनजातीय नेता बिरसा मुंडा की जयंती भी होती है। इस वर्ष 'झारखंड @25' थीम के साथ राज्य के गठन की 25वीं वर्षगांठ-रजत जयंती मनाई गई। वर्ष 2025 में झारखंड में आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे और सामाजिक योजनाओं में उल्लेखनीय प्रगति हुई। इसमें 7.5% आर्थिक वृद्धि का अनुमान, 'झारखंड @25' थीम के साथ स्थापना दिवस का रजत जयंती समारोह, और 1.45 लाख करोड़ रुपये के बजट के साथ कृषि-तकनीक पर जोर देते हुए किसान मेले का आयोजन शामिल है। रेलवे और सड़क परियोजना कार्यों में काफी प्रगति हुई। राज्य में रोजगार के मोर्चे पर होमगार्ड भर्ती के अवसर बढ़े। 2025-26 के वित्तीय वर्ष में राज्य में अर्थव्यवस्था में 7.5% वृद्धि का अनुमान है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। राज्य में 2025-26 के लिए 1.45 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया, जिसमें व्यय में 12 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य है। साथ ही राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 10 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है।

बुनियादी ढांचा और विकास

सड़क परियोजनाएंः सोनपुर बीघा से चतरा होते हुए बंगाल तक 610 किमी लंबा एक्सप्रेसवे और सारंगढ़-रायपुर फीडर रूट जैसी परियोजनाएं प्रगति पर हैं। कोयला परिवहन के लिए 452 किमी लंबी रेलवे लाइन परियोजना भी क्रियान्वित हो रही है। राज्य में कृषि और ग्रामीण विकास पर काफी जोर दिया जा रहा है। इसी सिलसिले में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने आदिवासी किसानों के लिए बेहतर तकनीक, बीज और कृषि-उद्यमिता पर केंद्रित किसान मेले आयोजित किए। राज्य में कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचारों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जबकि बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश जारी रहा। वित्तीय प्रबंधन और विकास दर में भी काफी सुधार हुआ।

> आज का दिन हमारे पुरखों के संघर्ष, बलिदान और आत्मसम्मान को नमन करने का अवसर है। धरती आबा बिरसा मुंडा, सिदो-कान्हू और फुलो-झानो जैसे वीरों की विरासत से प्रेरित होकर हमारा झारखण्ड आज विकास, संस्कृति और पहचान की नई ऊँचाइयों को छू रहा है। अबुआ सरकार हर मंईया के सम्मान, बच्चों की शिक्षा, युवाओं के रोजगार और परिवारों की सुरक्षा के लिए संकल्पित है। हम सब मिलकर अपने पुरखों के सपनों का समृद्ध और सशक्त झारखण्ड बनायेंगे। जय झारखण्ड!
>
> **हेमन्त सोरेन**
> मुख्यमंत्री, झारखण्ड

विधेयकों की मंजूरी पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति द्वारा मांगे गए संदर्भ पर एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपालों पर कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती। हालांकि संविधान पीठ ने अपने सर्वसम्मत फैसले मे यह भी कहा कि सांविधानिक प्राधिकारी राष्ट्रपति-राज्यपाल, राज्य विधानसभाओं से पारित विधेयकों को अनिश्चितकाल के लिए नहीं रोक सकते। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की संविधान पीठ ने कहा कि संविधान में मंजूर मान लिए जाने का कोई सिद्धांत नहीं है। यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल तय समय में किसी विधेयक पर कार्रवाई नहीं करते तो उसे स्वतः स्वीकृत नहीं माना जा सकता। संविधान पीठ ने कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय को अपने समक्ष आए किसी भी मामले में पूर्ण न्याय के लिए कोई भी आवश्यक आदेश पारित करने की व्यापक शक्ति देता है लेकिन संवैधानिक शक्तियों के इस्तेमाल के राष्ट्रपति-राज्यपाल के आदेशों को अनुच्छेद 142 के तहत मिली शक्तियों के जरिए किसी भी तरह बदला नहीं जा सकता।

उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि राज्यपालों के पास संविधान के अनुच्छेद के तहत तीन विकल्प हैं, विधेयकों को मंजूरी देना, उन्हें राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजना या मंजूरी रोक कर अपनी टिप्पणियों के साथ विधानसभा में वापस भेजना। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि संविधान में इसकी समय सीमा तय न होने और राज्यपाल की इस शक्ति के इस्तेमाल के तरीके स्पष्ट न होने से इस अदालत के लिए अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपालों को दी गई शक्तियों के इस्तेमाल पर न्यायिक रूप से समय सीमा तय करना सही नहीं होगा। हालांकि न्यायालय ने कहा कि राज्यपालों की ओर से विधेयक को एकतरफा तरीके से रोकना संघवाद का

उल्लंघन होगा। अगर राज्यपाल अनुच्छेद 200 में तय प्रकिया का पालन किए बिना विधानसभा से पारित विधेयक रोकते हैं, तो यह संघीय ढ़ांचे के हितों के खिलाफ होगा।

शीर्ष अदालत ने कहा कि जब राज्यपाल काम नहीं करना चाहते तो संवैधानिक अदालत सीमित न्यायिक समीक्षा कर सकती है। वह मामले के मेरिट में गए बिना राज्यपाल को काम करने का सीमित निर्देश दे सकती है। संविधान पीठ ने कहा कि राज्यपालों के पास विधानसभाओं से पारित विधेयकों पर रोक लगाने की पूर्ण शक्ति नहीं है।

उच्चतम न्यायालय ने महत्वपूर्ण राय रखी कि राष्ट्रपति या राज्यपाल की कार्रवाई न्यायिक परीक्षण के दायरे में नहीं आती। उसने कहा कि न्यायिक समीक्षा तभी की जा सकती है, जब विधेयक अधिनियम की शक्ल ले ले। शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जब कोई विधेयक अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की ओर से रिजर्व किया जाता है तो राष्ट्रपति इस पर रिव्यू मांगने को बाध्य नहीं हैं पर वह किसी अन्य वजह से रिव्यू मागंना चाहते हैं तो मांग सकते हैं।

उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश शीर्ष न्यायालय के ही दो न्यायाधीशों की खंडपीठ के आदेश के बाद राष्ट्रपति द्वारा मांगे गए रेफरेंस पर दिया है। जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने 8 अप्रैल को तमिलनाडु राज्य बनाम राज्यपाल के मामले में कहा था कि अगर राज्यपाल किसी विधेयक पर मंजूरी नहीं देते या उसे रिजर्व रख लेते हैं और यह विधेयक अगर दोबारा भेजा जाता है तो उन्हें एक महीने के अंदर उस पर फैसला लेना होगा। पीठ ने राष्ट्रपति के लिए भी समय सीमा तय करते हुए कहा था कि उन्हें भी राज्यपाल की ओर से उनके विचार के लिए रखे गए विधेयकों पर रेफरेंस मिलने की तिथि से तीन महीने के भीतर फैसला लेना होगा। खंडपीठ ने कहा था कि अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल तय समय सीमा में विधेयकों पर कार्रवाई नहीं करते तो उन्हें स्वतः मंजूर मान लिया जाएगा। खंडपीठ ने फैसले में कहा था कि तमिलनाडु के राज्यपाल का 10 विधेयकों पर मंजूरी न देने का फैसला असंवैधानिक और मनमाना है। पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत शक्ति का इस्तेमाल कर उन विधेयकों का पारित होना मंजूर घोषित कर दिया था।

शीर्ष न्यायालय ने कहा कि संविधान में इसकी समय सीमा तय न होने और राज्यपाल की इस शक्ति के इस्तेमाल के तरीके स्पष्ट न होने से इस अदालत के लिए अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपालों को दी गई शक्तियों के इस्तेमाल पर न्यायिक रूप से समय सीमा तय करना सही नहीं होगा। हालांकि न्यायालय ने कहा कि राज्यपालों की ओर से विधेयक को एकतरफा तरीके से रोकना संघवाद का उल्लंघन होगा।

इसी आदेश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने अनुच्छेद 143(1) के तहत दी गई शक्तियों का इस्तेमाल कर उच्चतम न्यायालय को रेफरेंस भेजा था कि क्या विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल पर समय सीमा तय की जा सकती है। 14 सवाल उठाते हुए उन्होंने इस पर शीर्ष अदालत की राय मांगी थी।

-द इमेज ब्रांडिंग

सियासत वाली पराली

ठंड की दस्तक के साथ ही, धान की कटाई और पराली जलाई के बीच आई दिवाली पर खतरनाक स्तर तक पहुंचे प्रदूषण के लिए फिर पराली को ही जिम्मेदार ठहराने में पंजाब और दिल्ली की राज्य सरकारें इस बार आमने-सामने रहीं। यह सच है कि पराली के चलते दोनों राज्यों के अलावा भी कई राज्य इसका प्रदूषण भुगत रहे हैं। लेकिन पंजाब-दिल्ली की सरकारें बजाए सुलह के एक दूसरे को दोषी ठहरा, प्रदूषण से कैसे निपटेंगी? आसमान से निगरानी और लाइव तस्वीरों के इस दौर में भी सच सामने होने के बावजूद राजनीतिक बयानबाजी बेहद हैरानगी भरी है। ये भी तथ्य है कि इस बार फसल अवशेष जलाने की सबसे अधिक घटनाएं मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में देखी गई।

सच है कि प्रदूषण की दमघोटू हवा इसके प्रभाव में आने वाले हर किसी को तकलीफ देती है। यह भी सही है कि कोरोना के बाद बहुतेरे लोगों में प्रदूषण सहन करने की क्षमता भी घटी है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सरकारें बयानों से बचाव करें। हालाकि इस बार दिल्ली में क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश की बात की जा रही थी जो नाकाम रही। फिर भी देखना होगा आगे यह तकनीक कितनी कामयाब होती है। लेकिन प्रदूषण को लेकर यह स्थाई विकल्प हो पाए, ऐसा लगता नहीं है।

इधर सुप्रीम कोर्ट ने भी बीते बरस, दिल्ली में बढ़े वायु प्रदूषण पर केंद्र को कड़ी फटकार लगाई तो पंजाब और हरियाणा सरकारों को भी चेताया। बावजूद इसके न तो काबू पाया जा सका न ही कोई विकल्प खोजा गया। अदालत में पेश जवाब पर ही सवाल खड़े होना लाजिमी थे जो हुए। फिलहाल दिल्ली में दिवाली के बाद से ही प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंचना बेहद चिंताजनक है। 301 से ऊपर का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इण्डेक्स(एएक्यूआई) इमरजेंसी स्थिति मानी जाती है जबकि अभी यह 450 के पार पहुंची हुई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि न केवल एनसीआर बल्कि दूसरे क्षेत्रों में भी प्रदूषण बढ़ा हुआ है। पंजाब भी बुरी तरह से इसकी गिरफ्त में है। लेकिन दिल्ली के मुकाबले वहां प्रदूषण अभी कम है।

केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड के आंकड़ों से पता चलता है कि दिल्ली में प्रदूषण में गिरावट विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों से काफी अधिक है। जबकि दिल्ली सहित नौ शहरों में यह पिछले महीने से ही 300 के पार रह रही है। वहीं देश में शिलांग की हवा सबसे साफ रही है जबकि भारत के 256 शहरों में से केवल 23 प्रतिशत में ही हवा साफ है यानी 77 प्रतिशत में वायु गुणवत्ता खराब है। गनीमत है कि बीच-बीच में बदलते मौसम से हालात बदल रहे हैं।

समझना होगा कि प्रदूषण के लिए केवल भारत ही नहीं पाकिस्तान की पराली का धुंआ भी जिम्मेदार है। नासा की एक रिपोर्ट, वर्ल्डव्यू एनिमेशन, सेटेलाइट तस्वीरें, चंडीगढ़ पीजीआई और पंजाब यूनिवर्सिटी के शोध से भी साफ हो गया है कि भारतीय पंजाब के मुकाबले पाकिस्तानी पंजाब में पराली ज्यादा जलती है। इस पर पड़ोसी देश पर भी लगाम की जरूरत है।

लेकिन ये होगा कैसे?

आखिर साफ हवा के लिए अ तक की कैसी कोशिशें हैं कि सालों साल से यह मसला बजाए सुलझने के हर बार नए आरोपों में घिर जाता है? रही बात सरकारों की तो केन्द्र या राज्य की सरकारें किसानों को लेकर दावा कुछ भी करें लेकिन किसानों की अपनी समस्याएं हैं। संसाधनों की कमीं से जूझते छोटे-मध्यम किसानों को भला ऋण कैसे मिलेगा ताकि पराली से विभिन्न उत्पाद बनाने वाली मशीनें खरीद सकें? किसानों की अपनी मजबूरी है।

खेती मौसम पर निर्भर है और एक-दो दिन का बिगड़ा मौसम महीनों की मेहनत पर पानी फेर देता है। इसी चलते किसान भी तुरंत पराली जलाने को मजबूर होते हैं। अगली फसल की बुवाई की जल्दबाजी में मौसम के

हालातों से जूझते किसान दूसरी फसल के लिए बहुत कम वक्त के चलते जानते-समझते मजबूरन पराली जलाने को विवश होते हैं।

दिल्ली में वायु प्रदूषण दशकों पुराना मुद्दा है। 1985 में भी आवाज उठी थी। जब कीर्ति नगर जैसे घने रिहायशी क्षेत्र में एक फटीलाईजर संयंत्र की जहरीली हवा से लोग बीमार होने लगे। तब सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एम.सी. मेहता ने अदालत में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान ही एक प्लांट से गैस रिसी और तीस हजारी कोर्ट के एक वकील की जान चली गई। कइयों की हालत बिगड़ी। इसके बाद कई कंपनियों पर प्रतिबंध लगा। आबादी वाले क्षेत्र में क्लोरीन, सुपर क्लोरीन, ओलियम, फॉस्फेट जैसी जहरीले उत्पाद बनाने पर रोक लगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने को मौलिक अधिकार बनाया।

धरातल पर देखें तो सिवाय कागजी योजना बनाने, बैठकें और आखिर में आरोप-प्रत्यारोप से ज्यादा भला अब तक क्या हासिल हुआ है? न तमाम प्रभावित राज्य सरकारें और न ही केन्द्र, पराली के दूसरे उपयोग किसानों को समझा पाया। क्लाउड सीडिंग से कृत्रिम बारिश की बातें करने वाली दिल्ली सरकार भी खतरनाक स्तर तक प्रदूषण से फौरी राहत भी नहीं दिला पाई। बजाए आपसी तू-तू, मैं-मैं के पराली संग्रहण, इसके व्यावसायिक उपयोग के उपाय तलाशे जाते तो शायद इसे जलाने की नौबत ही न आती। पराली मुद्दा गंभीर जरूर है लेकिन निदान असंभव नहीं? पर वायु प्रदूषण केवल पराली ही नहीं वाहनों, फैक्टरियों और अन्य कार्बन उत्सर्जन से भी बढ़ता है। काश, सरकारी तंत्र और हुक्मरान यह समझ पाते!

-द इमेज ब्रांडिंग

डिजिटल अरेस्ट के निशाने सीनियर सिटीजन

पुणे के एक 83 वर्षीय बुजुर्ग की मौत डिजिटल अरेस्ट का शिकार बनने के लगभग एक महीने बाद हो गई। साइबर पुलिस के अनुसार, पीड़ित रिटायर्ड सरकारी अधिकारी थे, जिनसे धोखेबाजों ने झांसा देकर 1। 2 करोड़ रुपये की ऑनलाइन ठगी की थी। यह घटना तब सामने आई जब उनकी पत्नी ने पति की मौत के एक सप्ताह बाद शिकायत दर्ज कराई। अधिकारियों ने बताया कि अगस्त में बुजुर्ग को एक कॉल आया, जिसमें कॉलर ने खुद को कोलाबा पुलिस स्टेशन का अधिकारी बताया। उसने कहा कि बुजुर्ग का नाम एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में सामने आया है।

जब पीड़ित ने आरोप से इनकार किया, तो उन्हें वीडियो कॉल पर दो अन्य व्यक्तियों ने धमकाया। एक ने खुद को आईपीएस अधिकारी बताया, जबकि दूसरे ने कहा कि वह सीबीआई का अधिकारी है। दोनों ने दंपति को चेतावनी दी कि यदि वे सहयोग नहीं करेंगे, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके बाद उन्हें घंटों वीडियो कॉल पर रखा गया और बताया गया कि उन्हें डिजिटल अरेस्ट रखा गया। बैंक खातों की जांच के नाम पर धोखेबाजों ने उन्हें 16 अगस्त से 17 सितंबर के बीच अलग-अलग खातों में कुल 1। 19 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया। कहा गया कि जांच पूरी होने के बाद पैसा लौटा दिया जाएगा।

साइबर पुलिस के मुताबिक, घटना का पता चलने पर अधिकारियों ने दंपति को एफआईआर दर्ज करने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने कहा कि वे बेटी के विदेश से लौटने के बाद ऐसा करेंगे। दुर्भाग्यवश, कुछ दिनों बाद बुजुर्ग को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि मौत और ठगी के बीच सीधा संबंध नहीं बताया जा सकता, लेकिन मामले में साइबर ठगों के खिलाफ जांच जारी है।

गौरतलब है कि 'डिजिटल अरेस्ट' नाम के एक बड़े रैकेट में विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है । 'डिजिटल अरेस्ट' घोटाले ने पहले ही देश में भय का माहौल पैदा कर रखा है। जनवरी से अगस्त 2025 के बीच देश में ऐसे करीब 400 मामले दर्ज किए गए। बताया जा रहा है कि इन अपराधों में कई सौ करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी 55 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को निशाना बना रहे हैं और जिन्हें डिजिटल दुनिया के बारे में बहुत कम जानकारी है। 'डिजिटल अरेस्ट' घोटाले का तरीका बहुत ही सुनियोजित हैः साइबर अपराधी लोगों के मन में डर पैदा करते हैं, खुद को पुलिस अधिकारी बताते हैं और पीड़ितों को फर्जी आधार कार्ड भेजते हैं, वे कहते हैं कि पीड़ित के बैंक खातों से करोड़ों नशे का लेन-देन हुआ है, यहां तक कि वे पीड़ितों को विश्वास दिलाने के लिए फर्जी कोर्ट के आदेश भी भेजते हैं। ऐसी घटनाएं कई जगहों पर हुई हैं और धोखाधड़ी की संख्या करोड़ों में है। कानून के तहत डिजिटल गिरफ्तारी की अनुमति नहीं होती, पुलिस या कोई भी सुरक्षा एजेंसी इस तरह से किसी को गिरफ्तार नहीं करती हैं। इस जानकारी के अभाव में साइबर अपराधी रिटायर्ड अफसरों और कर्मचारियों या पुराने कारोबारियों पर 'डिजिटल अरेस्ट' की चाल का इस्तेमाल करते हैं। वरिष्ठ नागरिक अक्सर प्रौद्योगिकी या कानूनी प्रावधानों के बारे में पर्याप्त रूप से जागरूक नहीं होते हैं। इससे उन्हें धोखा देना आसान हो जाता है।

इसी तरह, साइबर अपराधी कई लोगों को लूटने के लिए नए हथकंडे अपनाते हैं और ऐसा करने के लिए वे 'डिजिटल अरेस्ट' की चाल का उपयोग करते हैं। अपराधियों के ये गिरोह पुलिस, ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग, सेना के अधिकारी बनकर, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां, अवैध सामान का पता लगने का झूठा आरोप लगा कर पीड़ित को वीडियो कॉल करते हैं और उन्हें 24 घंटे अपने घर में बंद रहने के लिए कहा जाता है। साइबर अपराधी वीडियो कॉल पर किसी पुलिस स्टेशन या सीबीआई जैसी एजेंसी से बात करने का दिखावा करते हैं। साइबर अपराधी फिरौती मांगते हैं और पैसे नहीं देने पर उन्हें वास्तविक गिरफ्तारी की धमकी देते हैं, इसलिए कई लोग साइबर अपराधियों के नए हेरफेर का शिकार हो जाते हैं और उनके गले में लाखों-करोड़ों रुपये डाल देते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के अंबाला में फर्जी कोर्ट के आदेशों के जरिए नागरिकों की डिजिटल गिरफ्तारी के मामलों को गंभीरता से लिया है, जो न्यायिक प्रणाली में जनता के विश्वास की नींव को कमजोर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को डिजिटल गिरफ्तारी मामलों की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया है। अदालत ने डिजिटल गिरफ्तारी के मामलों में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दर्ज एफआईआर का विवरण भी मांगा है। उसने कहा है कि राज्य की पुलिस को 'डिजिटल अरेस्ट' के फर्जी स्वरूप के बारे में जागरूकता पैदा करना चाहिए और स्कूलों और कॉलेजों में कार्यशालाओं, प्रदर्शनों, प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रमों और प्रचार का आयोजन करके नागरिकों को इसके बारे में जागरूक बनाना चाहिए ताकि बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक या अन्य लोग साइबर अपराधियों के जाल में न फंसें।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार, देशभर में साइबर अपराधों के कई हजार मामले दर्ज किए गए हैं जो पिछले वर्ष के मामलों की तुलना में कई गुना अधिक हैं। यह वृद्धि डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग और साइबर जागरूकता की कमी को दर्शाती है। विशेष रूप से वृद्धजनों के बीच जो डिजिटल अरेस्ट, फिशिंग (phishing cyber crime) और वित्तीय धोखाधड़ी जैसे अपराधों का शिकार हो रहे हैं।

एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, 2018 से ही साइबर अपराधों में निरंतर वृद्धि देखी गई है। हालांकि, सीनियर सिटीजन के खिलाफ साइबर अपराधों के विशिष्ट आंकड़े एनसीआरबी द्वारा अलग से नहीं रखे जाते जिससे इस समस्या की गंभीरता को पूरी तरह समझना चुनौतीपूर्ण है। फिर भी हाल के मामलों जैसे मध्य प्रदेश में एक बुजुर्ग से 45 लाख रुपये की ठगी, वृद्धजनों के प्रति संवेदनशीलता को उजागर करते हैं।

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है। इसलिए, साइबर अपराधों की रोकथाम और जांच मुख्य रूप से राज्यों की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं, जिनमें भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना भी शामिल है। इसके तहत, 'नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल' और 'सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम' लॉन्च किए गए हैं, जिन्होंने शिकायतों को प्रोसेस करके लोगों के कई करोड़ रुपये लुटने से बचाए हैं। वित्तीय धोखाधड़ी की त्वरित शिकायतों के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1930 भी शुरू किया गया है।

केंद्र सरकार ने साइबर जागरूकता बढ़ाने के लिए कई अभियान भी शुरू किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अक्टूबर, 2024 को 'मन की बात' में डिजिटल अरेस्ट की समस्या का उल्लेख किया था। इसके साथ ही, दूरसंचार विभाग के सहयोग से 19 दिसंबर, 2024 से कॉलर ट्यून अभियान शुरू किया गया जो हिंदी, अंग्रेजी और 10 क्षेत्रीय भाषाओं में साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता फैला रहा है। अन्य पहलों में सोशल मीडिया, समाचार पत्र विज्ञापन, दिल्ली मेट्रो में घोषणाएं और कनॉट प्लेस में राहगीरी समारोह शामिल हैं। वृद्धजनों को साइबर ठगों से बचाने के लिए मजबूत पासवर्ड, टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और संदिग्ध लिंक से बचने की सलाह दी जा रही है।

जेएनयू छात्र संघ चुनाव में कैसे 'राइट' पर भारी पड़ा लेफ्ट

नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में इस साल के छात्रसंघ चुनाव नतीजों ने फिर इतिहास दोहरा दिया। राइट विंग के उम्मीदवारों को हाशिये पर ढकेल कर यहां के विद्यार्थियों ने लेफ्ट की विचारधारा को तवज्जो दी। वामपंथी छात्र संगठनों के साझा गठबंधन लेफ्ट यूनिटी ने चारों केंद्रीय पदों पर जीत दर्ज कर एक बार फिर साबित किया कि जेएनयू की राजनीति में अभी भी लाल विचारधारा की जड़ें गहरी हैं। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) को एक भी केंद्रीय पद पर जीत नहीं मिल सकी, जो उसके लिए पिछले कुछ वर्षों में सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। यह केवल एक चुनावी नतीजा नहीं, बल्कि बदलते रुख, विचारधारात्मक संघर्ष और छात्र राजनीति के रुझान का संकेत है।

पिछले पांच वर्षों में जेएनयू की राजनीति में जिस तरह के उतार-चढ़ाव देखे गए, उसने इस बार के नतीजों को और दिलचस्प बना दिया। 2020 के बाद से विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव लगातार राजनीतिक खींचतान का केंद्र रहे हैं। कभी एबीवीपी ने कैंपस में अपनी उपस्थिति मजबूत की, तो कभी वाम छात्र संगठन आपसी मतभेदों से जूझते दिखे। मगर इस बार हालात उलट गए। वामदलों ने पहली बार बेहद संगठित रणनीति अपनाई कर एकता बनाए रखते हुए हर संकाय और हर हॉस्टल स्तर तक गहराई से काम किया। यही कारण रहा कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव, चारों पदों पर लेफ्ट यूनिटी के उम्मीदवारों ने एबीवीपी को बड़े अंतर से हराया।

अध्यक्ष पद पर वाम उम्मीदवार अदिति मिश्रा की जीत सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही। अदिति जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज से शोध कर रही हैं और उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान फीस वृद्धि, शोध छात्रवृत्ति, हॉस्टल में सुविधाओं की कमी और छात्र सुरक्षा जैसे मुद्दों को केंद्र में रखा। उन्होंने कहा कि 'जेएनयू का संघर्ष सिर्फ विचारों का नहीं, बल्कि शिक्षा को सबके लिए सुलभ बनाने का है।' उनका सीधा और भावनात्मक संदेश छात्रों के दिल में उतर गया। दूसरी ओर, एबीवीपी की उम्मीदवार तन्या कुमारी राष्ट्रवाद और संगठनात्मक अनुशासन की बात करती रहीं, पर उनकी बातों में वह सादगी और जमीनी जुड़ाव नहीं दिखा जो अदिति के अभियान में झलक रहा था। इस बार के चुनाव में एक दिलचस्प बात यह रही कि मुद्दों का फोकस नारेबाजी से हटकर व्यावहारिक समस्याओं पर रहा।

पिछले वर्षों में जहां बहस 'देशविरोधी' और 'राष्ट्रभक्ति' जैसे मुद्दों तक सीमित रह जाती थीं, इस बार छात्र अपने वास्तविक कैंपस जीवन की दिक्कतों पर ज्यादा मुखर रहे। हॉस्टल फीस, रिसर्च फंड, लैब की स्थिति, और छात्र संगठनों की पारदर्शिता पर गहन चर्चा हुई। वाम संगठनों ने इस बदलाव को भांपते हुए अपने अभियान को 'स्टूडेंट्स फॉर स्टूडेंट्स' की थीम पर केंद्रित किया, जबकि एबीवीपी पारंपरिक नारों और रैलियों तक सिमटी रह गई। मतदान प्रतिशत में कमी भी इस चुनाव का एक दिलचस्प पहलू रहा। इस बार लगभग 67 प्रतिशत विद्यार्थियों ने मतदान किया, जो पिछले वर्षों की तुलना में कुछ कम था। विश्लेषकों के अनुसार, यह कमी बताती है कि छात्र राजनीति में अब विचारधारा से ज्यादा 'काम करने वाले' नेतृत्व की तलाश बढ़ रही है। वाम संगठनों ने इस भावना को समझा और युवाओं से सीधे संवाद किया और क्लास टू क्लास कैंपेन, कैफे चर्चाएं, और सोशल मीडिया पर सक्रिय अभियान से माहौल बनाया।

जेएनयू के चुनाव परिणामों का असर सिर्फ इस विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं रहता। ऐतिहासिक रूप से यह विश्वविद्यालय देश के अन्य विश्वविद्यालयों की छात्र राजनीति की दिशा तय करता रहा है। जब जेएनयू में लेफ्ट का झंडा बुलंद होता है, तो इलाहाबाद, हैदराबाद, कोलकाता और भोपाल जैसे शहरों में भी उसकी गूंज सुनाई देती है। इसी साल हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी एबीवीपी को अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एबीवीपी ने ठोस जीत दर्ज की, मगर जेएनयू में उसकी हार ने छात्र राजनीति के समीकरणों को फिर उलझा दिया है। एबीवीपी की इस हार ने उसके अंदर आत्मचिंतन की लहर पैदा की है। संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों का कहना है कि यह हार केवल चुनावी नहीं, संगठनात्मक चेतावनी भी है। वाम संगठनों की सक्रियता और एकजुटता ने उसे घेर लिया है। हालांकि, एबीवीपी ने यह

दावा भी किया कि उसने स्कूल काउंसलर की कई सीटें जीती हैं और यह संकेत है कि संगठन की जड़ें अभी भी मजबूत हैं। परंतु केंद्रीय पदों पर हार ने यह साबित किया कि जेएनयू के मुख्य नेतृत्व पर अब वामपंथ का वर्चस्व एक बार फिर स्थापित हो गया है। कैंपस में जीत की घोषणा होते ही वामपंथी कार्यकताओं ने लाल झंडों और नारेबाजी के साथ पूरे परिसर को उत्सव में बदल दिया। छात्रों ने 'लाल सलाम' के नारे लगाए और देर रात तक

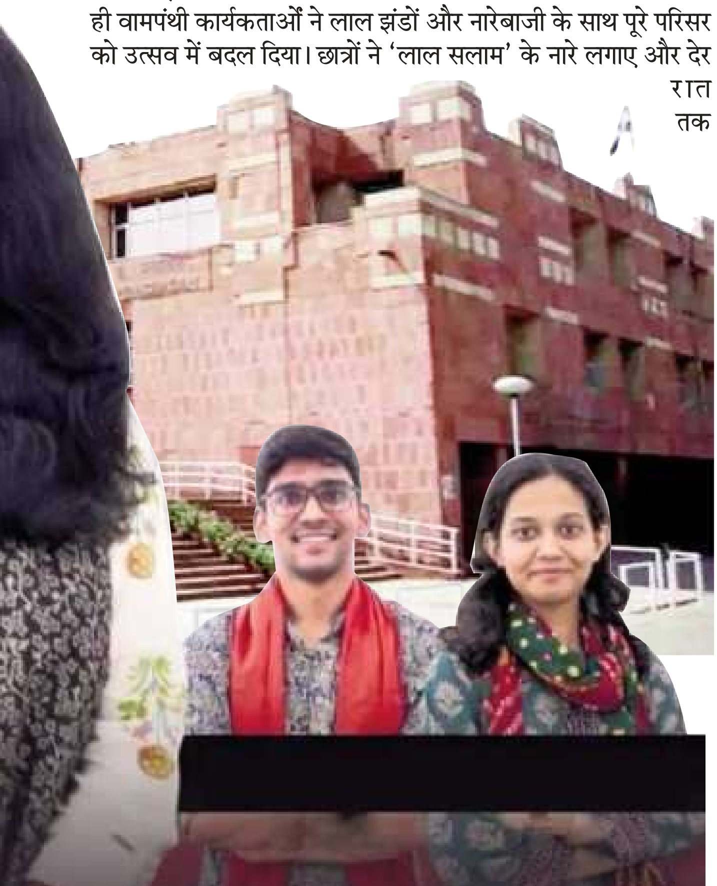
[redacted]

जश्न मनाया। दूसरी ओर, एबीवीपी के कार्यकर्ता शांत दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि वे संगठन फिर से मजबूत करेंगे और छात्रों के मुद्दों को लेकर संघर्ष जारी रखेंगे। यह तस्वीर भारतीय छात्र राजनीति की असली आत्मा दिखाती है, जहां हार के बाद भी उम्मीद बनी रहती है और हर चुनाव एक नई कहानी लिखता है।

पिछले पांच वर्षों में हुए बदलावों की ब्यार अब साफ दिखती है। 2019 से लेकर 2025 तक, जेएनयू ने कई वैचारिक प्रयोग देखे हैं, कभी एबीवीपी ने अपनी पकड़ बढ़ाई, कभी लेफ्ट यूनिटी में दरार आई, तो कभी एनएसयूआई और अन्य समूहों ने गठबंधन की कोशिश की। पर इस बार छात्र वर्ग फिर से वैचारिक रूप से वाम झुकाव की ओर लौटा है। इसका कारण शायद यह भी है कि बढ़ती महंगाई, शिक्षा का व्यावसायीकरण और रोजगार की कमी जैसे मसले अब युवाओं को सीधे प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में वाम विचारधारा उन्हें अपने करीब खींचने में कामयाब रही है। जेएनयू के इस चुनावी परिणाम का संदेश स्पष्ट है, छात्र राजनीति में एक बार फिर विचारों की ताकत ने जीत दर्ज की है।

सत्ता या संगठन नहीं, बल्कि मुद्दों और संवेदनाओं ने निर्णायक भूमिका निभाई। यह बदलाव सिर्फ जेएनयू के गलियारों तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर देशभर के विश्वविद्यालयों में महसूस होगा। भविष्य में जब छात्रसंघ चुनाव फिर होंगे, तो यह परिणाम संदर्भ के रूप में याद किया जाएगा कि कैसे जेएनयू ने फिर से बताया कि राजनीति केवल जीतने का नहीं, सोच बदलने का जरिया भी है। इस जीत और हार से परे एक बात स्पष्ट हुई है कि भारतीय विश्वविद्यालयों में छात्र राजनीति अभी भी जिंदा है, सक्रिय है और विचारों से भरी हुई है। जेएनयू के इस लाल परचम ने दिखा दिया है कि बदलाव की बहार फिर लौट आई है। एबीवीपी के लिए यह ठहराव आत्ममंथन का क्षण है, और वाम छात्र संगठनों के लिए यह जिम्मेदारी का दौर। आखिरकार, जो जीतता है उसे अगली सुबह उम्मीदों का बोझ भी उठाना पड़ता है और यही असली राजनीति है, जो जेएनयू के हर कोने में सांस ले रही है।

-द इमेज ब्रांडिंग

पुतिन की भारत यात्रा और समझौते

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी थीं। भारत और अमेरिका के तनावपूर्ण संबंधों और भारत पर रूसी तेल खरीदने को लेकर 50 प्रतिशत अमरीकी टैरिफ के बीच पुतिन लगभग चार साल बाद दिल्ली पहुंचे। समय की कसौटी पर खरा उतरे मित्र देश के नेता के स्वागत के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी खुद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। दोनों नेता एक साथ कार में सवार हो कर रात्रिभोज के लिए प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे। दूसरे दिन राष्ट्रपति पुतिन का राष्ट्रपति भवन में समारोह पूर्वक स्वागत किया गया। महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पण के बाद राष्ट्रपति पुतिन का भारत में कार्यक्रम विधिवत शुरू हुआ। राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ उनकी 23वीं भारत-रूस वार्षिक बैठक में दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को सैन्य और रक्षा साझीदार से आगे बढ़ाते हुए बहुआयामी बनाने के ढ़ांचे पर सहमति बनी। बातचीत में रक्षा क्षेत्र में सहयोग के नए रास्ते तलाशने की प्रक्रिया जारी रखने, आर्थिक और कृषि क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने, द्विपक्षीय कारोबार वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने, प्राथमिकता व्यापार समझौता जल्द करने और एक दूसरे की आवश्यकता अनुरूप प्रशिक्षित श्रमिकों की आपूर्ति पर सहमति व्यक्त की गई। अभी भारत और रूस का आपसी व्यापार 68 अरब डॉलर का है। बैठक में 16 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए और चार घोषणाएं हुईं। राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को तेल-गैस की निर्बाध आपूर्ति का आश्वासन दिया।आतंकवाद के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की मुहिम को पुतिन का समर्थन मिला। दोनों नेताओं ने आतंकवाद के हर स्वरूप के विरुद्ध शून्य सहनशीलता की नीति अपनाने और विश्व बिरादरी से इसके समर्थन की अपील की। वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों के बीच दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुई वार्ता में भारत-रूस की 'विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी' को और व्यापक बनाने का निर्णय लिया गया।

दोनों देशों के बीच हुए अहम समझौतों में

1. रूस के उद्योग आवश्यकता अनुसार भारत प्रशिक्षित कामगारों की आपूर्ति करेगा
2. दोनों देश गैर-कानूनी तौर पर श्रमिकों की आवाजाही रोकने में

सहयोग करेंगे

3. खाद्य उत्पादों की सुरक्षा और गुणवत्ता में सहयोग होगा ताकि भारत का रूस को निर्यात बढ़े

4. भारतीय कंपनी के लिए रूस में उर्वरक संयंत्र लगाने की अनुमति दी गई

अन्य महत्वपूर्ण घोषणाओं में

1. भारत रूसी पर्यटकों को 30 दिनों के लिए ई-वीजा देगा

2. रूसी नागरिकों को समूह पर्यटन वीजा देने की घोषणा की गई

3. वर्ष 2030 तक भारत-रूस आर्थिक सहयोग के तहत विशेष कार्यक्रम आरंभ किया जाएगा।

वार्ता में दोनों नेताओं ने ऊर्जा स्रोतों, कीमती पत्थरों और धातुओं सहित खनिज संसाधनों में उत्पादक और पारस्परिक रूप से लाभप्रद द्विपक्षीय व्यापार के महत्व के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं की विश्वसनीयता के लिए महत्वपूर्ण कच्चे माल के महत्व पर गौर किया।

ऊर्जा साझेदारी

दोनों पक्षों ने ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक सहयोग पर संतोष जताते हुए तेल और तेल उत्पाद, तेल शोधन और पेट्रोकेमिकल प्रौद्योगिकी, तेल क्षेत्र सेवाएं और अपस्ट्रीम प्रौद्योगिकी और संबंधित इन्फ्रास्ट्रक्चर, एलएनजी और एलपीजी से संबंधित इन्फ्रास्ट्रक्चर, अपने देशों में विभिन्न मौजूदा परियोजनाओं, भूमिगत कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी, परमाणु परियोजनाओं आदि जैसे क्षेत्रों में भारतीय और रूसी कंपनियों के बीच मौजूदा और संभावित सहयोग पर केंद्रित चर्चा की।

परिवहन और संपर्क

दोनों पक्षों ने इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांस पोर्ट कॉरिडोर, चेन्नई-व्लादिवोस्तोक पूर्वी समुद्री गलियारे और उत्तरी समुद्री मार्ग के लिए संपर्क में सुधार और बुनियादी ढांचे क्षमता बढ़ाने के लिए लॉजिस्टिक लिंक के विस्तार में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने रूस और भारत के रेलवे के बीच लाभदायक सहयोग का जिक्र किया, जिसका उद्देश्य पारस्परिक रूप से लाभकारी प्रौद्योगिकी विनिमय क्षेत्र में साझेदारी स्थापित करना है।

रूसी सुदूर पूर्व और आर्कटिक में सहयोग

दोनों पक्षों ने रूसी संघ के सुदूर पूर्व और आर्कटिक क्षेत्र में व्यापार और निवेश सहयोग तेज करने की तत्परता की पुष्टि की।

असैन्य परमाणु सहयोग, अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग

दोनों पक्षों ने ईंधन चक्र, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र और गैर-ऊर्जा अनुप्रयोगों के संचालन के लिए परमाणु ऊर्जा सहयोग व्यापक बनाने की पुष्टि की । दोनों पक्षों ने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रमों, उपग्रह नेविगेशन और ग्रहों की खोज सहित शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष के उपयोग में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और रूस के अंतरिक्ष विभाग 'रोस्कोस्मोस' के बीच बढ़ती साझेदारी का स्वागत किया और रॉकेट इंजन के विकास, उत्पादन और उपयोग में पारस्परिक लाभकारी सहयोग में प्रगति का जिक्र किया।

रक्षा सहयोग

दोनों पक्षों ने रूस में निर्मित हथियारों और रक्षा उपकरणों के रखरखाव के लिए कल-पुर्जे, औजारों, पूरक सामग्रियों और अन्य उत्पादों के भारत में संयुक्त निर्माण को प्रोत्साहित करने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और भारतीय सशस्त्र बलों की आवश्यता पूरी करने के लिए संयुक्त उद्यमों की स्थापना के साथ ही पारस्परिक रूप से मित्र देशों को निर्यात करना भी शामिल है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोगः

दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सरकार-से-सरकार, शिक्षा जगत और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। उभरती प्रौद्योगिकियों और उन्नत विनिर्माण के लिए दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदाओं की खोज, प्रसंस्करण और रिसाइक्लिंग प्रौद्योगिकियों में सहयोग मजबूत करने में रुचि दिखाई। उन्होंने डिजिटल प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग और विकसित करने की भी पुष्टि की। दोनों पक्षों ने फिल्म उद्योग में सहयोग विस्तारित करने के विचार का समर्थन किया, जिसमें संयुक्त फिल्म निर्माण और भारत एवं रूस में आयोजित अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में आपसी भागीदारी शामिल है। शिक्षा के क्षेत्र में भारत और रूस के बीच पारंपरिक रूप से मजबूत संबंधो को विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के स्तर पर जारी रखने पर सहमति व्यक्त की गई। अमरीकी और यूरोपीय देशों के दबाव के बीच राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा में भारत का रूस के प्रति समर्थन और रूस की भारत के लिए गहरी मित्रता परिलक्षित हुई। रूस को अलग-थलग करने की रणनीति के तहत तमाम प्रतिबंधों के बावजूद भारत का रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी है और भारतीय सेना को आज भी रूस से मिले हथियारों पर ज्यादा भरोसा है। भारत ने हर देश के साथ अपनी अलग कूटनीति के सिद्धांत को बढ़ाते हुए स्पष्ट कर दिया कि वह अपने मित्र को साथ लेकर चलेगा। उसने फिर दोहराया कि वह शांति का पक्षधर है,तटस्थ नहीं।

-द इमेज ब्रांडिंग

क्या शुरू होगी नई न्यूक्लियर रेस?

वैश्विक स्तर पर दुनियां के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा जिस मुद्दे पर हो रही है, वह है अमेरिका का 33 वर्षों के बाद पुनः परमाणु परीक्षण शुरू करने का आदेश। जिस देश ने दशकों तक पूरी दुनिया को परमाणु हथियारों से दूर रहने की नसीहत दी, आज वही देश फिर से न्यूक्लियर बमों की गूंज सुनना चाहता है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिकी सेना को परमाणु परीक्षण तुरंत शुरू करने का आदेश देने के बाद वैश्विक समुदाय में एक प्रकार की हलचल मच गई है। रूस से लेकर चीन, उत्तर कोरिया से लेकर ईरान तक हर देश की निगाह अब अमेरिका की ओर है। सवाल यह है कि क्या यह कदम दुनिया को एक बार फिर से 'न्यूक्लियर रेस' में धकेल देगा? दुनियां यह देख रही है कि अमेरिका का दोहरा मापदंड 'दूसरों को रोको, खुद करो' नीति का परिणाम क्या निकलेगा, अमेरिका दशकों से वैश्विक राजनीति में 'न्यूक्लियर नैतिकता' का सारथी बनकर बैठा रहा है। उसने हमेशा अन्य देशों पर परमाणु हथियार न बनाने का दबाव बनाया। चाहे वह ईरान हो, उत्तर कोरिया हो या कभी भारत। अमेरिकी नीतियों ने हमेशा यह कहा कि परमाणु हथियार मानवता के लिए खतरा हैं। लेकिन अब वही अमेरिका, जो खुद को 'ग्लोबल पीस कीपर' कहता है, नए परीक्षणों के आदेश जारी कर रहा है। यह कदम न केवल उसकी विदेश नीति की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि उसके 'डबल स्टैंडर्ड' की अंदरुनी नीति भी उजागर करती है। अमेरिका की यह नीति इतिहास में कई बार देखी जा चुकी है, जब वह अंतरराष्ट्रीय संधियों से खुद को अलग कर लेता है और दूसरों पर उसका पालन करना थोपता है। उदाहरण के लिए, ट्रंप प्रशासन ने 2018 में ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकलकर वैश्विक स्थिरता को बड़ा झटका दिया था। आज 2025 में, वही नीति एक नए रूप में फिर लौट आई है।

हमें ट्रंप की सामरिक रणनीति के संकेत को समझना होगा कि आखिर अमेरिका ने अब ऐसा कदम क्यों उठाया? आखिरी बार अमेरिका ने 1992 में नेवादा में परमाणु परीक्षण किया था। उसके बाद उसने अंतरराष्ट्रीय दबाव और 'कंप्रीहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी' के तहत परीक्षण रोक दिए थे। लेकिन अब ट्रंप का यह आदेश बताता है कि वाशिंगटन का इरादा वैश्विक सैन्य वर्चस्व को दोबारा स्थापित करने का है।अमेरिकी खुफिया एजेंसियों और रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, चीन और रूस की तेजी से बढ़ती परमाणु क्षमता ने ट्रंप प्रशासन को यह कदम उठाने के लिए प्रेरित किया है। रूस ने अपने हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल 'एवंगार्ड' और 'सरमाट' की घोषणा कर दी है, जबकि चीन भी 'डोंगफेंग-41' जैसी लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण कर चुका है। ट्रंप शायद यह दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका अब भी 'मिलिट्री टेक्नोलॉजी' में सर्वश्रेष्ठ है।

अगर हम वैश्विक प्रतिक्रिया, रूस का जवाब और दुनिया की चिंता को समझने की कोशिश करें तो, जैसे ही अमेरिका के परमाणु परीक्षण के आदेश की खबर फैली, सबसे पहले रूस ने इसका कड़ा जवाब दिया। रूसी विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कहा कि यदि अमेरिका परीक्षण शुरू करता है, तो रूस भी 'तुरंत जवाबी परमाणु परीक्षण' करेगा। यह बयान सीधे संकेत देता है

कि दुनियां फिर से 'कोल्ड वॉर' जैसे दौर की ओर बढ़ सकती है। रूस की इस प्रतिक्रिया के बाद चीन ने भी अपनी सैन्य प्रयोगशालाओं में 'सुरक्षा और क्षमता वृद्धि' के नाम पर तैयारी शुरू कर दी है। वहीं, यूरोप के देशों,विशेषकर फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने संयुक्त बयान, जारी कर कहा कि यह फैसला 'वैश्विक स्थिरता के लिए घातक' साबित हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भी गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि '33 वर्षों की शांति को तोड़ने वाला यह कदम, दुनिया को एक और हथियारों की दौड़ में झोंक सकता है।'न्यूक्लियर रेस पर गौर करने से लगता है कि क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? यदि हम इतिहास पर नजर डालें तो यह समझना कठिन नहीं कि हर बार जब किसी शक्ति ने अपने हथियारों की ताकत दिखाने की कोशिश की है, तो उसका परिणाम 'वैश्विक अस्थिरता' के रूप में सामने आया है।1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा किए गए दो बम विस्फोटों ने मानव सभ्यता की दिशा ही बदल दी। उसके बाद 1945 से अब तक लगभग 2,000 से अधिक परमाणु परीक्षण दुनिया भर में किए गए हैं। इनमें से आधे से अधिक परीक्षण अकेले अमेरिका ने किए। आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका ने करीब 1,030 परमाणु परीक्षण, रूस (पूर्व सोवियत संघ) ने 715, फ्रांस ने 210, चीन ने 45, ब्रिटेन ने 45, भारत ने 6, पाकिस्तान ने 6, और उत्तर कोरिया ने घोषित 6 परीक्षण किए हैं। यह सूची बताती है कि परमाणु शक्ति केवल 'रक्षा' का माध्यम नहीं रही, बल्कि यह देशों के 'राजनीतिक दबाव' और वैश्विक दबदबा कायम करने का उपकरण बन चुकी है।

अगर हम विश्व के लिए संभावित खतरे को समझने का प्रयास करें तो,अगर अमेरिका ने वाकई में अपने परमाणु परीक्षण फिर शुरू किए, तो यह डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करेगा। रूस, चीन, उत्तर कोरिया और शायद ईरान भी अपनी क्षमता बढ़ाने में जुट जाएंगे। यह न केवल हथियारों की दौड़ तेज करेगा, बल्कि 'न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स','रेडिएशन लीकेज', व 'आर्थिक दबाव' जैसी समस्याओं को भी जन्म देगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखने के लिए काम करने वाली इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जैसी संस्थाओं की भूमिका भी कमजोर पड़ जाएगी। विश्लेषक मानते हैं कि ट्रंप का यह फैसला केवल सैन्य दृष्टि से नहीं, बल्कि

रूस, चीन, उत्तर कोरिया और शायद ईरान भी अपनी क्षमता बढ़ाने में जुट जाएंगे। यह न केवल हथियारों की दौड़ तेज करेगा, बल्कि 'न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स','रेडिएशन लीकेज', व 'आर्थिक दबाव' जैसी समस्याओं को भी जन्म देगा।अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखने के लिए काम करने वाली इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जैसी संस्थाओं की भूमिका भी कमजोर पड़ जाएगी।

राजनीतिक उद्देश्य से भी प्रेरित है। 2025 की अमेरिकी राजनीति में ट्रंप 'मजबूत राष्ट्रवाद' व 'अमेरिका फर्स्ट' के नारे को पुनर्जीवित कर रहे हैं। न्यूक्लियर टेस्ट का आदेश उसी एजेंडा का हिस्सा हो सकता है, जिससे वे अमेरिका को फिर से 'अजेय शक्ति' के रूप में पेश कर सकें। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह 'अजेयता' वास्तव में शांति की ओर ले जाएगी या दुनिया को एक नए संकट में धकेलेगी? अमेरिका द्वारा 33 साल बाद परमाणु परीक्षण दोबारा शुरू करने का आदेश एक 'ऐतिहासिक मोड़' है,ऐसा मोड़ जो या तो दुनिया में विचलन पैदा करेगा उसे तीसरे विश्व युद्ध जैसी अंधकारमय स्थिति में झोंक देगा। भारत जैसे देशों के लिए भी यह एक गंभीर चुनौती है कि वे अपनी 'जिम्मेदार न्यूक्लियर नीति' को बनाए रखते हुए विश्व शांति की दिशा में कैसे आगे बढ़ें। अब विश्व समुदाय को तय करना होगा कि वह हथियारों की दौड़ में शामिल होगा या विवेक और संवाद की राह चुनेगा। एक बार यदि न्यूक्लियर रेस शुरू हो गई, तो मानव सभ्यता को खुद अपने बनाए हथियारों से मिटने में देर नहीं लगेगी?

-द इमेज ब्रांडिंग

धर्मेंद्र - एक युग का अंत

कई दशकों तक लोगों के दिलों पर राज करने वाले लोकप्रिय अभिनेता का 24 नवम्बर 2025 को निधन हो गया। उनकी आयु 89 वर्ष थी और केवल दो सप्ताह में वे 90 वर्ष पूरा करने वाले थे। उन्होंने अपने मुंबई स्थित आवास में अंतिम सांस ली। हाल ही में सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था। उनका अंतिम संस्कार मुंबई में जुहू स्थित शवदाहगृह में किया गया। धर्मेंद्र के निधन से एक युग का अंत हो गया है।

धर्मेन्द्रः बॉलीवुड का 'ही-मैन', जिसकी मुस्कान परदे को रोशन कर देती थी

मुंबई की चकाचौंध में कई सितारे आते-जाते रहते हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ इतिहास नहीं बनाते–वो यादों में बस जाते हैं। धर्मेन्द्र ऐसा ही एक नाम है। एक ऐसा अभिनेता, जिसकी सादगी, दिलकश मुस्कान और दमदार स्क्रीन-प्रेजेन्स ने भारतीय सिनेमा को कई रंग दिए।

1950 के दशक के अंत में अभिनय के सपने लिए पंजाब से मुंबई आए धर्मेन्द्र ने 'दिल भी तेरा, हम भी तेरे' (1960) से अपनी फिल्मी यात्रा शुरू की। उस समय उनका आकर्षण ही उनका बड़ा हथियार बना–बिना किसी नाटकीयता के सहज अभिनय।

1960-70 के दशक में वे रोमांटिक हीरो के रूप में दर्शकों की धड़कन बने। 'अनुपमा', 'सत्यकाम', 'चुपके-चुपके' जैसी फिल्मों में उनकी संवेदनशीलता दिखी, तो 'शोले', 'यादों की बारात', 'पत्थर और पायल' ने उनका एक्शन-स्टार वाला रूप सामने रखा। यहीं से उन्हें मिला उनका मशहूर खिताब–बॉलीवुड का ही-मैन। उनके अंदर की ईमानदार भावनाएं और कैमरे के सामने की सहज ऊर्जा ने उन्हें बीते छह दशक में लगभग 300 से अधिक फिल्मों में एक अलग पहचान दी।

सर्वाधिक लोकप्रिय भूमिकाएं और फिल्में

वीरू-'शोले' (1975)

धर्मेन्द्र के करियर का सबसे यादगार किरदार। वीरू की बेफिक्र मस्ती, दोस्ती के लिए जान देने का जज्बा और बसंती से प्यार–सब कुछ मिलकर इस किरदार को अमर बना देता है।

डॉ. पारस-'अनुपमा' (1966): यह वो भूमिका है जिसने सिद्ध किया कि धर्मेन्द्र सिर्फ हैण्डसम हीरो नहीं, बल्कि एक भावुक और गहराई से अभिनय करने वाले कलाकार भी हैं।

अमल-'सत्यकाम' (1969): हृषिकेश मुखर्जी की इस क्लासिक फिल्म में उन्होंने आदर्शवाद की लड़ाई लड़ने वाले इंसान का दर्द और संघर्ष बेहद वास्तविक तरीके से निभाया।

'चुपके-चुपके' (1975) का शरारती प्रोफेसरः हल्की-फुल्की कॉमेडी में धर्मेन्द्र का टाइमिंग देखने लायक था। उनकी संजीदा छवि के बीच यह फिल्म आज भी कॉमेडी प्रेमियों की पसंदीदा है।

हेमा मालिनी और धर्मेन्द्रः फिल्मी पर्दे से वास्तविक जीवन तक जब भी पर्दे पर रोमांटिक जोड़ों की बात आती है, धर्मेन्द्र-हेमा मालिनी की जोड़ी हमेशा याद की जाएगी। 'सीता और गीता', 'शोले', 'शराफत', 'जुगनू', 'दोस्त', 'राजा जानी' जैसी फिल्मों में उनकी केमिस्ट्री ने दर्शकों को दीवाना बनाया। उनकी ऑन-स्क्रीन जोड़ी इतनी पसंद की गई कि लोगों ने उन्हें 'ड्रीम गर्ल' और 'ही-मैन' की परफेक्ट पेयरिंग कहना शुरू

कर दिया। धीरे-धीरे यह फिल्मी रिश्ता निजी जीवन में बदल गया और दोनों ने साथ एक खुशहाल परिवार बसाया। उनकी प्रेम कहानी आज भी फिल्मों की मशहूर प्रेम कहानियों की तरह सुनाई जाती है।

धर्मेन्द्र के बारे में प्रसिद्ध लोगों की राय

अमिताभ बच्चन

अमिताभ ने कई बार कहा है कि धर्मेन्द्र उनके पसंदीदा सहकलाकारों में से रहे। ₹शोले₹ के दौर को याद करते हुए वह बताते हैं कि धर्मेन्द्र की ऊर्जा और हंसमुख स्वभाव सेट पर सबको प्रफुल्लित रखता था।

हृषिकेश मुखर्जी

इस दिग्गज निर्देशक ने कहा था कि धर्मेन्द्र की आंखें इतनी अभिव्यक्तिपूर्ण हैं कि वो बिना संवाद के भी कहानी कह देती हैं। 'सत्यकाम' उनका पसंदीदा धर्मेन्द्र-परफॉर्मेंस था।

जीतेंद्र

जीतेंद्र अक्सर धर्मेन्द्र की दोस्ती और बड़े दिल की तारीफ करते हैं। वह कहते हैं–'धर्मेन्द्र जैसे इंसान फिल्म इंडस्ट्री में बार-बार पैदा नहीं होते।'

हेमा मालिनी

हेमा जी ने कई बार इंटरव्यू में कहा –'धरमजी की सादगी और उनका दिल ही उन्हें इतना खास बनाता है।

धर्मेन्द्रः सिर्फ एक अभिनेता नहीं, एक युग

धर्मेन्द्र का प्रभाव केवल उनकी फिल्मों तक सीमित नहीं रहा–वह भारतीय सिनेमा के एहसास थे। उनकी मृदुभाषिता, विनम्रता और सादगी ने उन्हें दर्शकों का 'दिल का हीरो' बनाया। वे उन सितारों में थे जिनका नाम लेते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है।

धर्मेन्द्र की प्रमुख फिल्में

अनुपमा (1966)
सत्यकाम (1969)
आँखें (1968)

कॉमेडी में उनकी बेहतरीन फिल्में

चुपके-चुपके (1975)
दिल्लगी (1978)

एक्शन और मसाला सिनेमा

शोले (1975)
यादों की बारात (1973)
जुगनू (1973)
राजा जानी (1972)

हेमा मालिनी के साथ सुपरहिट फिल्में

सीता और गीता (1972)
शराफत (1970)
राजा जानी (1972)
जुगनू (1973)
दोस्त (1974)
शोले (1975)
चरस (1976)
आजाद (1978)
अलीबाबा और चालीस चोर (1979)

➤ बाद के दौर की प्रमुख फि ल्में

जॉनी गद्दार (2007)
यमला पगला दीवाना (2011)

रॉकी और रानी की प्रेम कहानी (2023)

धर्मेन्द्र-हेमा मालिनीः प्रेम कहानी

हेमा मालिनी जब इंडस्ट्री में नई थीं, उनकी सुंदरता और सादगी ने पूरे फिल्म जगत को आकर्षित किया। धर्मेन्द्र भी उस समय एक स्थापित और बेहद लोकप्रिय अभिनेता थे। कहा जाता है कि दोनों की पहली मुलाकात फिल्म 'तुम हसीन मैं जवान' (1970) के सेट पर हुई। कैमरे के सामने शुरू हुआ यह रिश्ता धीरे-धीरे दिलों तक पहुंच गया।

हेमा मालिनी बताती हैं कि धर्मेन्द्र का सबसे बड़ा आकर्षण उनकी शर्मीली मुस्कान, संवेदनशीलता, और उनकी सच्ची इंसानियत थी। वहीं धर्मेन्द्र हेमा को 'ड्रीम गर्ल' ही नहीं, बल्कि 'अपने जीवन की सबसे खूबसूरत प्रेरणा' मानते रहे।

फिल्मों में अक्सर दोनों रोमांस से भरे किरदार निभाते, और दर्शक रियल-लाइफ में भी इस जोड़ी को देखने की इच्छा रखते। इंडस्ट्री में उनकी जोड़ी को सबसे लोकप्रिय ऑन-स्क्रीन पेयरिंग माना गया–वैसी जोड़ी जो राजझनर्गिस, दिलीप-मधुबाला की तरह अमर हो गई।

धीरे-धीरे यह रिश्ता इतना गहरा हुआ कि उन्होंने शादी कर ली।

हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू में कहा था–

'मैंने धर्मेन्द्र को इंसान के तौर पर चुना, अभिनेता के तौर पर नहीं। उनके दिल में बहुत प्यार है।'

भारतीय महिला क्रिकेट नई संभावना को सलाम

2 नवंबर 2025 का दिन भारतीय खेल जगत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज हो गया। उस दिन नवी मुंबई का डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी मैदान न केवल एक विश्व कप का साक्षी बना, बल्कि भारतीय महिला शक्ति की अजेय प्रतिभा और जज्बे का भी उसने प्रमाण देखा। शेफाली वर्मा ने 87 रन की पारी खेल कर विश्वकप को भारत के नाम कराने में अमूल्य योगदान दिया। शेफाली की यह पारी आत्मविश्वास से भरी होने के साथ-साथ लाजवाब रही। इसी के साथ स्मृति मांधना ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भारत के लिये सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी। उनकी टाइमिंग और कवर ड्राइव ने सबका दिल जीत लिया। वैसे टीम का हर खिलाड़ी इस रोमांचक जीत के लिये बधाई का पात्र है। निश्चित ही भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी महिला विश्व कप 2025 अपने नाम कर ऐसा इतिहास रचा, जो न केवल खेल का स्वर्णिम अध्याय है बल्कि सामाजिक परिवर्तन और नारी सशक्तिकरण की प्रेरक गाथा भी है। विश्व

विजेता बनने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट की टीम की चर्चा दुनिया के हर कोने में हो रही है।

यह जीत केवल एक ट्रॉफी भर नहीं, बल्कि उस नारी शक्ति का उद्घोष है जो वर्षों से अपने अस्तित्व को साबित करने में लगी थी। भारतीय बेटियों ने मैदान में दिखा दिया कि अब 'क्रिकेट का खेल' सिर्फ पुरुषों का क्षेत्र नहीं रहा, यह वह मंच है जहां नारी की प्रतिभा, रणनीति, धैर्य और आत्मविश्वास अपनी सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति पा रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर टीम को बधाई देते हुए कहा कि 'यह केवल क्रिकेट की जीत नहीं, बल्कि भारत की नारी शक्ति, परिश्रम और आत्मविश्वास की जीत है।' सच भी यही है कि यह विजय भारत की नई महिला चेतना का प्रतीक है, वह चेतना जो अब हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ रही है। अब भारतीय महिलाओं को हाशिया नहीं, पूरा पृष्ठ चाहिए और यह बात उन्होंने इस ऐतिहासिक जीत हासिल कर साबित किया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार महिला वनडे विश्व कप अपने नाम कर ऐतिहासिक जीत हासिल की है। भारत और दक्षिण-अफ्रीका का फाइनल विश्व कप मैच सदा के लिए इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों दर्ज हो गया है। हरमनप्रीत की कप्तानी में महिला

क्रिकेट टीम ने यह यादगार जीत हासिल की है। इससे पहले मिताली राज की कप्तानी में महिला क्रिकेट टीम 2005 और 2017 में फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन तब ट्रॉफी हाथ से फिसल गई थी। भारतीय महिला टीम टॉस हारने के बाद भी बल्लेबाजी के लिए उतरी और उसने 298 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। दक्षिण अफ्रीक की टीम इस आंकड़े को छू नहीं पाई। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर 47 साल के इंतजार को खत्म किया। इस महान सफलता के पीछे आईसीसी अध्यक्ष जय शाह की दूरदर्शी नीतियों और नेतृत्व का भी बड़ा योगदान है। उनके कार्यकाल में महिला क्रिकेट को वह सम्मान और अवसर मिले जिसकी वह वर्षों से हकदार थी। जय शाह ने न केवल संरचनात्मक सुधार किए बल्कि महिला क्रिकेट के लिए आधारभूत ढांचे, सुविधाओं और प्रोत्साहन योजनाओं को नई दिशा दी।

उन्होंने यह साबित कर दिया कि जब नेतृत्व में दृष्टि होती है, तो इतिहास बदलता है। इस विश्व कप में भारतीय खिलाड़ियों ने अपने खेल से दुनिया को चकित कर दिया। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने जिस साहस और सूझबूझ से टीम का नेतृत्व किया, वह प्रेरणादायक रहा। उनके बल्ले से निकले हर रन ने नारी शक्ति की धुन गाई।

स्मृति मांधना की क्लासिकल बल्लेबाजी ने विपक्षी गेंदबाजों को बेहाल कर दिया, जबकि युवा खिलाड़ी शैफाली वर्मा की आक्रामकता ने नई पीढ़ी की ऊर्जा को स्वर दिया। गेंदबाजी में रेणुका ठाकुर और पूजा वस्त्रकार की सटीक लाइन-लेंथ ने टीम को हर मुश्किल समय में संभाला, वहीं स्पिनर दीप्ति शर्मा ने अपनी जादुई गेंदों से विरोधियों के हौसले पस्त किए। इस टूर्नामेंट में भारत की फील्डिंग और फिटनेस भी अप्रतिम रही, जो यह दर्शाती है कि अब भारतीय महिला क्रिकेट केवल तकनीक नहीं, बल्कि रणनीति और दक्षता के सर्वोच्च मानकों पर खड़ी है।

महिला क्रिकेट खिलाड़ी नवीन क्षमताओं की नई उड़ान भरते हुए हर मन की मुराद पूरी कर रही है। यह जीत केवल एक उपलब्धि नहीं, बल्कि भारतीय खेल संस्कृति में परिवर्तन की दिशा का प्रतीक है। आज भारत की बेटियां छोटे कस्बों और गाँवों से निकलकर विश्व मंच पर चमक रही हैं। यह उस सामाजिक परिवर्तन का परिणाम है जिसमें परिवार, समाज और सरकार ने नारी खेल प्रतिभा को अवसर देना शुरू किया है। महिला विश्व कप 2025 ने यह सिद्ध कर दिया कि अब भारत में खेल सिर्फ 'मैदान' तक सीमित नहीं, यह राष्ट्रीय चेतना और गौरव का हिस्सा बन चुका है। यह नारी स्वाभिमान, श्रम और संघर्ष की कहानी है। क्रिकेट अब केवल पुरुषों की लोकप्रियता

मीडिया की भी बड़ी भूमिका है

महिला क्रिकेट को निरंतर प्रमुखता देना, खिलाड़ियों की कहानियों को सामने लाना, और समाज में इस भावना को मजबूत करना कि यह केवल खेल नहीं, बल्कि सशक्तिकरण का माध्यम है - यही अब आने वाले समय की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है।

जीत के पीछे अनेक अनकही कहानियां हैं

वह मां जो अपनी बेटी के लिए समाज की परवाह किए बिना बैट खरीदती है, वह पिता जो खेत बेचकर क्रिकेट किट दिलाता है, वह कोच जो बिना वेतन के खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करता है, और वे साथी खिलाड़ी जो रिजर्व में रहकर भी हर समय टीम के साथ खड़ी रहती हैं। यह जीत केवल मैदान पर खेलने वाली 11 खिलाड़ियों की नहीं, बल्कि उन हजारों सपनों की जीत है जो वर्षों से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। 2025 का यह वर्ष भारतीय खेलों के लिए स्वर्णिम वर्ष के रूप में दर्ज होगा। भारत की बेटियां अब सिर्फ़ इतिहास नहीं, भविष्य लिख रही हैं। उनकी यह विजय हर भारतीय के दिल में गर्व, प्रेरणा और उम्मीद की लौ जगा रही है।

अमनजोत कौर का परिवार जीत जश्न मनाता हुआ।

52 साल के इंतजार का अंत

नवी मुंबई की वो शाम अब हमेशा याद रखी जाएगी। 2 नवंबर 2025 वो तारीख जब भारत की महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्वकप का ताज अपने सिर पर सजाया। यह जीत केवल एक खेल का परिणाम नहीं थी, बल्कि 52 साल के लंबे इंतजार का अंत थी। यह जीत उस विश्वास की कहानी है, जिसे भारत की बेटियों ने अपने परिश्रम, साहस और हौसले से सच कर दिखाया। डी. वाई. पाटिल स्टेडियम में खेला गया यह फाइनल मैच पूरे देश की धड़कनों से जुड़ा था। टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। शुरूआती विकेट जल्दी गिरने से स्टेडियम में हल्की चिंता थी, लेकिन तभी शेफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा ने मोर्चा संभाल लिया। शेफाली की बल्लेबाजी में आत्मविश्वास झलक रहा था। उन्होंने 87 रन बनाकर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। दीप्ति शर्मा ने 58 रनों की समझदारी भरी पारी खेली और बाद में गेंदबाजी में भी अपना जलवा दिखाया। भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट पर 298 रन बनाए। लक्ष्य छोटा नहीं था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की टीम के इरादे भी बड़े थे। उनकी ओपनर लॉरा वोल्वार्ट ने शानदार अर्धशतक लगाया और कुछ देर के लिए भारतीय समर्थक खामोश हो गए। लेकिन रेणुका सिंह और पूनम यादव ने मिलकर खेल की दिशा बदल दी। दीप्ति शर्मा ने गेंदबाजी में कमाल करते हुए 5 विकेट चटकाए और साउथ अफ्रीका को 246 रनों पर रोक दिया। जैसे ही आखिरी विकेट गिरा, पूरा स्टेडियम तिरंगे के रंग में डूब गया। भारतीय टीम 52 रनों से जीत गई और यही 52 साल का प्रतीक बन गया, उस लंबे इंतजार का जो आखिरकार आज समाप्त हुआ।

मैदान पर जो हुआ, वह सिर्फ एक खेल की जीत नहीं थी। वह इतिहास की दिशा बदलने वाला क्षण था। जब हरमनप्रीत कौर ने ट्रॉफी उठाई, तो उनके आंसू सिर्फ खुशी के नहीं थे, वो उन सालों का बोझ थे, जब भारतीय महिला क्रिकेट को नजरअंदाज किया गया, जब उन्हें अभ्यास के लिए मैदान नहीं मिलते थे, जब सुविधाएं सीमित थीं और सवाल बहुत। आज उन सवालों का जवाब तिरंगे के रूप में आसमान में लहराया। यह जीत उन तमाम दिग्गज खिलाड़ियों की भी है जिन्होंने दशकों तक इस सपने के लिए मेहनत की। डायना एडुल्जी, मिताली राज, झूलन गोस्वामी, अंजुम चोपड़ा जैसी खिलाड़ियों ने जो बीज बोया, वह आज फल बनकर सामने आया। उनके संघर्ष ने आने वाली पीढ़ियों को राह दिखाई। अब वही राह और चौड़ी हो चुकी है।

का प्रतीक नहीं रहा, बल्कि महिलाओं की असाधारण योग्यता का उत्सव बन गया है। भारत की यह जीत उस भविष्य की ओर इशारा करती है जहां खेल, लिंग भेद से परे, केवल प्रतिभा और परिश्रम के आधार पर सम्मान पाएगा।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की यह ऐतिहासिक विजय केवल कप जीतने की कहानी नहीं है, यह उस भारत की घोषणा है जो अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने का साहस रखता है। यह जीत हर उस लड़की की प्रेरणा है जो गली के मैदान में क्रिकेट बैट थामे सपना देखती है कि एक दिन वह भी भारत के लिए खेलेगी। यह स्वर्णिम विजय हमें यह संदेश देती है कि भारत की नारी अब हर क्षेत्र में 'खेल बदलने' के लिए तैयार है। जय शाह जैसे सक्षम नेतृत्व और खिलाड़ियों की प्रतिभा से सुसज्जित यह टीम आने वाले समय में विश्व क्रिकेट का नया अध्याय लिखेगी, जहां हर शॉट में आत्मविश्वास होगा, हर गेंद में संकल्प, और हर जीत में भारत की बेटियों की दमकती मुस्कान। भारत की बेटियां अब सिर्फ खेल नहीं रही हैं बल्कि वे इतिहास रच रही हैं।

देश पर छा रहे अनेकानेक उजालों के बीच महिला विश्व कप 2025 रूपी उजाला देशवासियों को प्रसन्नता का प्रकाश दे गया। संदेश दे गया कि देश का एक भी व्यक्ति अगर दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ने की ठान ले तो वह शिखर पर पहुंच सकता है। विश्व को बौना बना सकता है। पूरे देश के निवासियों का सिर ऊंचा कर सकता है। महिलाओं की इस करिश्माई उपलब्धि के बाद अखबारों के शीर्ष में यह समाचार छपा और सबको लगा कि शब्द उन पृष्ठों से बाहर निकलकर नाच रहे हैं। भारतीय महिला खिलाड़ियों ने खिलाड़ीपन के लम्बे रन-अप को पल-पल जीया है। इस दौरान बहुत कुछ पीया है तभी वे विश्व विजेता बनी। वरना यहां तक पहुंचते-पहुंचते कईयों के घुटने घिस जाते हैं। एक बूंद अमृत पीने के लिए समुद्र पीना पड़ता है। सम्मान, पदवी, उपाधियां, अलंकरण बहुतों को मिलते हैं पर सही सीने पर सही तमगा और सही नाम के आगे सही संबोधन कभी-कभी लगता है। जैसा महिला विश्व कप 2025 की भारतीय महिला खिलाड़ियों के सीनों पर लगा है। जब भी कोई अर्जुन धनुष उठाता है, निशाना बांधता है तो करोड़ों के मन में एक संकल्प, एक एकाग्रता का भाव जाग उठता है और कई अर्जुन पैदा होते हैं। अपने देश में हर बल्ला उठाने वाला अपने को गावस्कर, तेंगुलकर विराट कोहली, रोहित समझता है, हर बॉल पकड़ने वाला अपने को कपिल-अर्शदीप, बुमराह समझता है। हॉकी की स्टिक पकड़ने वाला हर खिलाड़ी अपने को ध्यानचंद, हर टेनिस का रेकेट पकड़ने वाला अपने को रामानाथन कृष्णन समझता है। और भी कई नाम हैं, मिल्खा सिंह, पी.टी. उषा, प्रकाश पादुकोण, गीत सेठी, जो खेलों की महत्तम ऊंचाइयों पर पहुंचे। आज शेफाली हो स्मृति या फिर जेमिमा हो या दीप्ति आज मिसाल बन गयी हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को सलाम।

-द इमेज ब्रांडिंग

मेक्सिको की फातिमा बॉश बनी मिस यूनिवर्स 2025

थाईलैंड के बैंकॉक में 21 नवंबर 2025 को आयोजित एक भव्य समारोह में मेक्सिको की 25 साल की फातिमा बॉश फर्नांडीज मिस यूनिवर्स 2025 चुनी गईं। उन्होंने दुनिया भर की 130 सुंदरियों को पछाड़ते हुए यह ताज अपने नाम किया। इस जीत के साथ ही मिस यूनिवर्स जीतने वाली वह चौथी मैक्सिकन बन गईं। उन्होंने अपने आत्मविश्वास और शानदार प्रदर्शन से जजों का दिल जीता। हालांकि ताज की दावेदारी के दौरान उन्हें अपमान भी झेलना पड़ा। प्रतियोगिता से पहले एक आयोजक द्वारा फातिमा बॉश को डांटने का मामला सामने आया था, जिसके बाद अन्य प्रतियोगी उनके समर्थन में खड़ी हो गई थीं, और बाद में कुछ जजों ने भी इस्तीफा दे दिया था। इनमें से एक ने कहा कि प्रतियोगिता 'फिक्स्ड' है। ये विवाद थाई और मैक्सिकन मालिकों के बीच सांस्कृतिक और रणनीतिक मतभेदों से सामने आया। मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में मिस थाईलैंड फर्स्ट रनर-अप और मिस वेनेजुएला सेकेंड रनर-अप रहीं। भारत की मनिका विश्वकर्मा टॉप 30 में रहीं पर टॉप 12 में जगह बनाने में नाकाम रहीं। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 1952 में शुरू हुई थी और इस साल यह इसका 74वां संस्करण रहा। अमेरिका से शुरू हुई मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता और ब्रिटेन से शुरू हुई मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता, दुनिया की सबसे लंबे समय से चल रही सौन्दर्य प्रतियोगिताओं में शामिल है।

–द इमेज ब्रांडिंग

Miss Universe Winners from India

Lara Dutta - 2000

Sushmita Sen - 1994

Harnaaz Kaur Sandhu

2021

Harnaaz Kaur Sandhu is the 2021 Miss Universe from India. She was crowned Miss Universe, bringing India its third title in 21 years

नारद मुनि कहिन

नारद जी इस बार जब प्रभु श्री विष्णु के सम्मुख अपनी रिपोर्ट लेकर पहुंचे तो प्रभु को मुदित पाया हालांकि हैरानी की बात थी प्रभु के बगल में कोई मशीन रखी थी जो महीन आवाज में टिंग टोंग - टिंग टोंग से बदल कर ओम जय जगदीश हरे का धुन बजा रही थी। प्रभु का ध्यान अपनी ओर पाते ही नारद मुनि ने जयकारा लगाया-

'शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम।
लक्ष्मीकांत कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम,
वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम॥'

भगवन प्रसन्न हो कर बोले, आइए मुनिवर, कहिए क्या हाल है धरतीलोक का?

नारद जी कहने लगे, 'नारायण-नारायण! प्रभु, धरती लोक का हाल पूछिए मत। प्रभु, आज मैं आपके लिए एक ऐसी रिपोर्ट लाया हूं, जिसे सुनकर देवगण मास्क पहन लें और असुर भी एयर प्यूरीफायर ऑर्डर कर दें!'

प्रभु चौंक कर बोले, अरे क्या हो गया, इतने विचलित क्यों हैं मुनिवर?

नारद जी ने कहा क्या बताएं प्रभु वैसे तो संपूर्ण विश्व जलवायु के निरंतर खराब होने से परेशान है, पर आर्यावर्त अर्थात दिल्ली और उसके एनसीआर में तो स्थिति ऐसी है कि हवा कम, धुआं ज्यादा मिल रहा है। लगता है सांस देने वाला प्राण वायु भी अब छुट्टी पर चला गया है।

प्रभु ने विस्मय से पूछा,'हे नारद, क्या सच में हाल इतना खराब है?'

नारद जी बोले, 'प्रभु, 'खराब' तो अब पुरानी बात है। अब तो वायु गुणवत्ता 'अत्यंत खराब' से निकलकर 'विकटतम श्रेणी' की तरफ प्रस्थान कर रही है।

AQI इंडेक्स ऐसे उछल रहा है जैसे कलियुग का सेंसेक्स!' प्रभु बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं, बुजुर्गों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। लोग हाथों में बैनर, तख्तियां लिए इंडिया गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस उन्हें धकिया कर भगा रही है। जो नवयुवक-युवतियां पुलिस डाउन-डाउन कर रहे हैं उन्हें किसी का सपोर्टर बता कर घसीट कर गाड़ी में लाद कर थाने पहुंचाया जा रहा है।

खबर है कि ये फैशनबल एक्टिविस्ट अब कह रहे हैं कि हम तो डोंट हिड डोंट हिड पॉल्यूशन फिगर नारे लगा रहे थे और ठुल्ले भाईयों ने रिवोल्यूशन सुन लिया। हमें क्या लेना देना किसी इज्म से हम तो साफ हवा मांग रहे थे। पर अधिकारी कह रहे हैं कि तुम्हीं सिगरेट में कुछ मिला-विला कर पीकर देश का माहौल बिगाड़ रहे हो। असली पॉल्यूशन तो तुम्ही फैला रहे हो। ....नारद जी ने कहा, प्रभु जनरेशन जी भी अब भयाक्रांत हो गया है।

प्रभु गौर से रिपोर्टिंग सुनते रहे।

नारज जी ने कहा प्रभु सीपीसीबी का भी दम फूल रहा है। भगवन, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड–सीपीसीबी–की हालत देखकर तो दया आ जाती है। जैसे आपका वाहन गरुड़ ऊंची उड़ान भरता है, वैसे ही प्रदूषण भी ऊंची ऊंची उड़ान भर रहा है।... और उधर सीपीसीबी बेचारा नीचे-नीचे दौड़ रहा है–मशीनें लगा रहा है, अलर्ट निकाल रहा है–पर हवा कह रही है: 'पकड़ सकते हो तो पकड़ लो!'

प्रभु श्री नारायण ने मुख पर चिंता के भाव के साथ नारद जी की ओर देखा।

भगवान का ध्यान अपनी रिपोर्टिंग की ओर पाकर नारद जी और उत्साहपूर्वक कहने लगे प्रभु,

दिल्ली में तो हाल ऐसा है कि सुबह की धुंध नहीं, पार्टिकुलेट मैटर का परदा है। सांस लेने में दिक्कत नहीं–सांस खोजने में दिक्कत है। लोगों ने फेस मास्क महामारी में लगाया था, अब हवा के डर से पहना जा रहा है।

प्रभु बोले अरे इससे तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि बेहद खराब होगी।

नारद जी बोले, प्रभु, चीन में बीजिंग का हाल भी कमतर नहीं है। दरअसल जहां नव विकास है, वहीं अधिक प्राकृतिक दोहन है। पर प्रभु, पृथ्वी लोक इतने घनघोर प्रदूषण की आदी हो चुकी है कि अब कोई दूर की धूल भी दोषी ठहरा दी जाती है।... कहते हैं इथियोपिया के किसी 'हायली गुब्बी' जैसे ज्वालामुखी की राख के गुबार का असर भी वायुमंडल पर नजर आया है–लोग बोल रहे हैं कि यह हवा ऊपर की परतों में घूमती-घामती अब चीन की ओर बढ़ रही है।

अब यह वैज्ञानिक सत्य है या जनता का कल्पनात्मक 'आसमानी बहाना', यह तो धरा-लोक ही जाने–लोग वायु गुणवत्ता बिगड़ने पर दूर-दराज की राख तक को दोष दे रहे हैं। कहावत भी है – जब अपनी चिमनी ज्यादा धुआं छोड़े, तो पड़ोसी की रसोई को दोष दिया जाता है !

प्रभु ने चिंता प्रकट करते हुए कहा मुनिवर नारद, यह दृश्य तो सचमुच चिंताजनक है। कल्पना करिए, अगर यही हाल रहा तो धरती लोक में लोग हमें 'वायु शुद्धिकरण अवतार' लेने का निवेदन भेजेंगे।

नारद जी ने बॉस के सम्मुख खींसे निपोड़ते हुए कहा

'प्रभु, अवतार तो आपको लेना ही पड़ेगा–या फिर मानव लोक को समझाना पड़ेगा कि वायु शुद्धिकरण पेड़ लगाकर होता है, बहानों से नहीं !

और सीपीसीबी को भी कुछ दैवीय 'बूस्टर' दीजिए–वरना वह भी किसी दिन कह देगाः 'हमसे न हो पाएगा, प्रभु !

नारद जी ने कहा प्रभु, स्थिति ऐसी है कि हवा में PM 2.5 और PM 10 ऐसे नाच रहे हैं

जैसे फिल्मी आइटम नंबर पर कहर ढा रहे हों।

'हवा-हवाई' हवा-हवाई'

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिन-रात कह रहा है–'भईया, AQI देख लो–

आज 450 पार, कल 500 की रेस!
AQI की हालत देख लगता है
जैसे पुराना विलेन जोर से चिल्लाए–
'मोगैम्बो' घुट गया!'

नारद जी ने बात आगे जारी रखते हुए कहा प्रभु, वाहन ईंधन का 'फुल टैंक' भी कहर ढ़ा रहा है।

गाड़ियों ने तो कमाल कर दिया है, धुएं का उत्सर्जन ऐसे छोड़ रही हैं जैसे कह रही हों–

'आवारा धुआं हूं' उड़ता ही फिरूं' ...नारद जी कातर स्वर में बोले हे स्वामी

पेट्रोल-डीजल की महक अब इत्र नहीं,
सीधा आंखों में आंसू बनकर उतरती है।

प्रभु नारायण ने पूछा मुनिवर ये फसल अवशेष पराली का क्या चक्कर है, पहले तो यह केवल पंजाब तक सीमित रहता था। अब इसका क्या हाल है ?

नारद मुनि बोले, प्रभु पराली जलाना अब सर्वव्यापी हो गया है। अब यह हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान से लेकर बिहार तक व्याप्त हो गया है। क्या बताएं प्रभु, आपसे क्या छिपा है। कहते हैं कि तेरे प्यार में दिलदार जो है मेरा हाल-ए-जार ,कोई देखे या ना देखे अल्लाह देख रहा है।

तो प्रभु कहानी ये है कि -इक धुआं था, जो गांवों से शहरों तक आ गया, हमने समझा सर्दी है, पर ये प्रदूषण था, जाग गया। किसान बेचारे विवशता में पराली जलाएं, और शहर वाले हर साल नया बहाना बनाएं। उधर पराली का धुआं कह रहा है–'भाई, दोष मेरे सिर मत मढ़ो, समाधान सोचो !'

उधर दिल्ली सरकार की करोड़ों की मशीनें लगीं पर धुआं न माने हार, हर सुबह का मौसम बुलेटिन अब तापमान से ज्यादा प्रदूषण का रोमांचक थ्रिलर बन गया है। उस पर ग्रेडेड रिस्पॉस एक्शन प्लान ने तो और भी व्यंग्यात्मक दृश्य उत्पन्न कर रखा है। जैसे ही हवा बिगड़ती है,

ग्रैप अपनी किताब खोलकर नियम पढ़ देता है–
'स्टेज 1–हल्का प्रदूषण' → मास्क पहन लो
'स्टेज 2–खराब हवा' → कार कम चलाओ
'स्टेज 3–बहुत खराब' → निर्माण रोक दो
'स्टेज 4–गंभीर' → सब लोग घर में छुप जाओ
और जनता पूछती है–प्रभु, हवा कब सुधरेगी ?
'धुआं उठा नगर-गांव से, ढक ली नभ की छांव,
पार्टिकुलेट मैटर की इस भीड़ में, सांसें हुईं परेशान,
प्रभु करो कुछ वायु-हीलिंग, टूट गए इंसान।
हे विष्णो लोकपालक, करुणा करुता धाम,
शुद्ध करो वातास को, मिटे प्रदूषण-ग्राम।
जन-जन को दे ज्ञान तू, बचूं प्रदूषण-फंद,
प्रकृति फिर मुस्काय प्रभु, हो निर्मल यह आनंद।'

प्रभु विष्णु ने कहा कि यह तो ऐसा मुद्दा है, जिसका हल मिल जुल कर करना होगा।

नारद मुनि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यही तो दिक्कत है प्रभु, यहां भी डर्टी पॉलिटिक्स हो रही है। आपके भक्त नरेंद्र जी ने किसी और संदर्भ में कुछ दिनों पहले कह दिया था कि मौसम का मजा लीजिए। अब सोनिया जी और उनकी पार्टी संसद में प्रदूषण की समस्या पर चर्चा कराने की मांग कर रहे हैं।

कह रहे हैं किस मौसम का हाल देखें। धुएं में लिपटी दिल्ली में तो बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा है। साल दर साल हालात बदतर होते जा रहे है, हर साल बयानबाजी होती है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। इसी पॉल्युशन के मारे मेरा नन्हा बच्चा राहुल बार बार विदेश भागता है। सोनिया जी ने ताना मारते हुए ये भी कहा कि आपकी दिल्ली की रेखा सरकार ने क्लाउड सीडिंग से बारिश करा देने का भी दावा किया था, पर सब टांय टांय फिस्स हो गया... और यही हाल रहा तो कैपिटल को कहीं और शिफ्ट करना पड़ जाएगा।

उधर चंद्र बाबू आइडिया दे रहे हैं कि क्यों न अमरावती में ही दिल्ली की एक ब्रांच खोल दी जाए, काहे कि वहां पाल्यूशन-फ्री डेवलपमेंट हो रहा है, इस पर आपके एक और भक्त योगी जी ने भी कहा है कि इतनी दूर क्यों जाएंगे, अपने यूपी में ही राजधानी एक्सटेंशन की सोचिए ,पहले भी तो रही ही है। ....बाबा जी की महत्वाकांक्षाएं हिलोरें ले रही हैं।

दिल्ली में खराब वायु गुणवत्ता पर माता लक्ष्मी ने अंत में हस्तक्षेप करते हुए कहा, देखिए आप दोनों महानुभावों से कह देती हूं अंत में एयर पॉल्यूशन का ठीकरा दिवाली पर मत फोड़ देना। हां... नही, तो।

मामला गरमाते देख नारद जी ने वहां से निकल चलने में ही भलाई समझी। जयकारा लगाया नारायण-नारायण !'

प्रभु बोले चाय तो पीते जाइए, मुनिवर

नारद जी ने कहा नेक्सट टाइम प्रभु ! और उड़ चले अगली खबर लाने।

मल्लिका ने खोला फिल्म इंडस्ट्री का काला सच

बॉलीवुड में ग्लैमर के पीछे का डार्क साइड हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। कई स्टार्स ने अपने कास्टिंग काउच और एक्सपीरिएंस के जरिए इंडस्ट्री की कड़वी सच्चाई लोगों के सामने रखी है। इन्हीं में से एक हैं मल्लिका शेरावत, जिन्होंने पिछले साल अपने पुराने एक्सपीरिएंस शेयर करके फिल्म जगत की सोच पर सवाल खड़े कर दिए हैं।फिल्म 'मर्डर' से रातों-रात स्टार बनने वाली मल्लिका शेरावत ने पिछले साल राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी के साथ फिल्म 'विक्की विद्या का वो वाला वीडियो' से लंबे समय के बाद वापसी की थी। इसी फिल्म के प्रमोशन के दौरान उन्होंने कुछ ऐसे इंटरव्यूज दिए जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया।हाउटर फ्लाई के साथ एक इंटरव्यू में मल्लिका ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा एक चौंकाने वाला वाकया बताया था। उन्होंने कहा कि वहां महिलाओं की कामुकता को अकसर अपना कंटेंट बेचने या सीन को ग्लैमरस दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।एक्ट्रेस ने एक घटना याद करते हुए कहा- 'एक साउथ फिल्म की शूटिंग के दौरान, डायरेक्टर चाहते थे कि हीरो मेरी कमर पर रोटियां पकाते हुए नजर आए, ताकि मेरी हॉटनेस दिखाई जा सके। मैंने साफ मना कर दिया, लेकिन यह बताता है कि कुछ लोगों की मानसिकता क्या थी।'मल्लिका ने आगे कहा कि इंडस्ट्री में महिलाओं को अक्सर ग्लैमरस ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, और यही सोच उन्हें परेशान करती थी। उन्होंने इस मानसिकता के खिलाफ आवाज उठाई और बताया कि कैसे वो शुरूआत से ही समझौता करने से बचती रहीं।

'द पैराडाइज' में सोनाली ने काटा बवाल

टैलेंटेड डायरेक्टर श्रीकांत ओडेला, जिन्होंने हाल ही में दसरा जैसी बड़ी हिट दी थी, अब लेकर आ रहे हैं द पैराडाइज। इस फिल्म में नेचुरल स्टार नानी लीड रोल में नजर आएंगे। यह भारत की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक मानी जा रही है फिल्म दसरा की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद नानी और श्रीकांत ओडेला की यह एक और शानदार कोलैबोरेशन होने जा रही है। फिल्म को लेकर बढ़ते उत्साह के बीच मेकर्स ने हाल ही में लीड एक्ट्रेस सोनाली कुलकर्णी का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज किया है। अब यह सामने आया है कि उनका किरदार भारतीय सिनेमा के सबसे मजबूत और दमदार किरदारों में से एक होने वाला है। 'सोनाली कुलकर्णी का किरदार भारतीय सिनेमा के सबसे ताकतवर किरदारों में से एक है। फिल्म में वह मुख्य किरदार की मां की भूमिका निभा रही हैं, और उनका रोल आज के समय की 'शिवगामी' कहा जा सकता है।' द पैराडाइस का रॉ स्टेटमेंट रिलीज हुआ, जिसमें मुख्य किरदार की मां उसे वेश्या का बेटा बताती है। इस असरदार बयान के साथ हमें एक दमदार महिला किरदार की झलक मिली।

महिमा चौधरी की बेटी देख पागल हुआ आधा जमाना

इस समय बॉलीवुड सितारों के साथ-साथ बॉलीवुड के स्टार किड्स की भी खूब चर्चा होती है। भले ही काजोल और अजय देवगन की बेटी न्यासा देवगन हो या फिर रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी हों, सभी ग्लैमर वर्ल्ड में इन दोनों लाइमलाइट में बने हुए हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे स्टार्टड के बारे में बताने वाले हैं जो कि हमेशा लाइमलाइट से दूरी बनाए रखती हैं।दरअसल हम बात कर रहे हैं महिमा चौधरी की बेटी आर्यना चौधरी की। वह खूबसूरती में बिल्कुल अपनी मां महिमा चौधरी की तरह ही नजर आती है। चेहरे पर मासूमियत, खूबसूरत आंखें और हर किसी का दिल जीत लेने वाली मुस्कुराहट, महिमा चौधरी की बेटी की हर कोई खूब तारीफ करता हुआ नजर आता है।

Haldiram's
Banao
CHATPATE
PAL AUR
MEETHI
YAADEIN!
Pictures & presentation may not represent the actual product/portion.
Shop Online@www.haldiramsonline.com

RNI No. : DELBIL/2020/87310

IMAGE BRANDING

A PR and Advertising Company

We Create Brands

WELCOME TO IMAGE BRANDING

Products are made in the factory, But Brands are created in the mind.

We build your personal brand. Brand is perceptions, ideas, concepts, and visuals that distinguish one product from others in a market. So, the way you carry yourself, the way you speak, work, communicate and write, it all adds up to create a personality and ultimately establishes you as brand. It connects you with everyone and excludes nobody. Brand image is developed over time through sustained advertising campaigns and is authenticated through the consumers' experience.

Building a recognizable personal brand opens professional opportunities. Since younger generation are connected increasingly with internet, mobile, video and entertainment places, therefore careful campaign will be devised and run for mass customization and individual pull towards your personality and services and also the product you are associated with.

Read More

+91 8800224261

43-A, Amrit Nagar,
South Ex.Part-1,
New Delhi-110003.

www.imagebranding.co.in

Mail: imagebrandingindia@gmail.com